खण्ड-12 1200 01/08/16 संख्या-20

एकादश

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

भाग- 2

कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित

सोमवार, तिथि 20 जुलाई 1998 ई०

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 1998-99 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण में सम्मितिल अनुदान की मांगों पर वाद-विवाद एवं मतदानः मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग (स्वीकृत)

श्री तुलसी सिंह : प्रश्न यह है कि:-

"प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजना/योजनाओं के लिए" मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होनेवाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग अधिनियम, 1998 के उपबंध के अतिरिक्त 45,74000 (पैंतालीस लाख, चौहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाय।

यह प्रस्ताव राज्य पाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष : इस प्रथम अनुपूरक बजट के संबंध में कई कटौती प्रस्ताव हैं। मैं सदन को सूचित कर देता हूँ और चाहता हूँ कि इस अनुपूरक बजट में विभागों का मांग भी है। अभी सिर्फ मांग संख्या- 4 में प्राप्त कटौती प्रस्ताव पर वाद-विवाद होगा और शेष की व्यवस्था को हम अंत में गिलोटीन द्वारा करेंगे। मैं समझता हूँ कि इसपर आपलोगों की सहमति है। मांग संख्या 4 में श्रीमती चन्द्रमुखी देवी एवं राधा कृष्ण किशोर जी का कटौती का प्रस्ताव है। अतः श्रीमती चन्द्रमुखी देवी जी अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

कटौती-प्रस्तावः

राज्य सरकार की मंत्रिमंडल सचिवालय एवं सयम्वयनीति पर विचार विमर्श (अस्वीकृत)

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्वाव करती हूँ कि:-

"इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटायी जाय।"

अध्यक्ष महोदय, यह जो हमलोगों को प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी प्रस्तुत किया गया है, और उसपर हमलोग जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं, आज अगर बहस होता है और इतना आनन-फानन में कटौती प्रस्ताव को पेश करने के लिए कहा जा रहा है, इसके लिए आज मैं बिल्कुल ही तैयार होकर नहीं आयी थी लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, कहना चाहती हूँ मैं आज इस सरकार ने जो प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी प्रस्तुत किया है, और इसपर अपना कटौती प्रस्ताव पेश किया है, ऐसी परिस्थिति सरकार को किस परिस्थिति में आयी कि सारे विषयों को छोड़कर इसको ताख पर रखकर इस रूप में प्रथम अनुपूरक बजट को लाया गया, इसपर आज गौर करने की जरूरत है। और वहां की आम जनता भोग रही है उस क्षेत्र के रहनेवाले माननीय विद्यायको ने कहा है पर वाद-विवाद नहीं हो सका। आज बागमती और कोशी जैसी नदियां अपना भयावह रूप धारण कर लिया है और तटबंध टूटने की निरंतर शिकायत मिल रही है। भागलपुर और देवघर जानेवाला मार्ग बार-बार बंद हो जा रहा है जिससे कांवरियों को कष्ट हो रहा हैं इन सारी समस्याओं पर इस सदन में विशेषकर बाढ़ जैसी समस्या पर वाद-विवाद की आवश्यकता थी, जो नहीं हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में कहा था कि सारा बिहार बाढ़ से त्रस्त है और सरकार समय पर तटबंधों की सुरक्षा नहीं कर पाती है। यही इस सरकार की नियति रही है। बाढ़ को प्रकृति का रूप दे दिया गया है जिसका नतीजा है कि बिहार हर वर्ष बाढ़ की भीषण विशीषिका झेल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र से हो कर आ रही हूं। शहरों की एक-एक सड़कें जर्जर हो गई हैं, शहरों की नालियां बजबजा रही है। नागरपालिका ने कूड़ा उठाने की व्यवस्था नहीं की है। आज एक-एक सड़कें, एक-एक नालियां जर्जर हो गई हैं। महोदय, शहरों में रहनेवाले विधायक जब अपने अपने क्षेत्र में जायेंगे तब उनको पता लगेगा। हमारे खगड़िया की स्थिति यह है कि वहां पर नगरपालिका ने कूड़ा उठाने के लिए कूड़ेदानों की व्यवस्था कर दी है। कूड़ेदान रख दिये गये हैं कूड़ा डालने की तो व्यवस्था हो गई है।

लेकिन नगरपालिका ने अभी तक यह व्यवस्था नहीं की है कि उन कूड़ों को उठा कर किसी सुरक्षित स्थान पर फेंक दिये जाएं। महोदय, ऐसे समय में जब कि सारी नालियां बजबजा रही हैं, सारे-सड़कें मरम्मती के अभाव में जर्जर हो गई हैं, लोग चल नहीं पा रहे है। महोदय, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पटना के किसी भी गली में निकल जाएं, किसी भी सड़क पर निकल जाएं, महोदय, आप कंकड़बाग डूबा हुआ है। वहां रहनेवाले लोग परेशान है। पत्रकारों ने बताया कि जब वे सुबह ऑफिस के लिए निकले हैं तो हाफ पैंट पहन कर ऑफिस आते है और ऑफिस आने पर फुलपैंट पहनते है। तो यह स्थिति यह पटना की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि नगर से आने वाले विधायक ज्यादा त्रस्त हैं। पहले भी मैंने कहा कि हमारे लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। नगरपालिकाओं को चुनाव वर्षो से नहीं कराया गया। इसलिए मै आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि अगर इस सरकार को चलना है, ठीक है, हमारी मंशा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों की विकास करें। मेरी भी अपनी अपेक्षा है कि ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो । लेकिन मेरी मंशा यह बिल्कुल नहीं है कि नगर क्षेत्र की दुर्दशा करके ग्रामीण क्षेत्रों की विकास हो। लकिन नगर क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाये। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैं यह कहना चाहती हूं कि सरकार ने जान-बूझ कर ऐसा किया है। अध्यक्ष महोदय, भा0ज0पा0 के अधिकांश विधायक नगर क्षेत्र से आते हैं। इस सरकार की मंशा रही है कि नगर क्षेत्र से आने वाले विधायक नगर क्षेत्र से आते हैं। इस सरकार की मंशा रही है कि नगर क्षेत्र से आने वाल विधायक ....

अध्यक्ष : आप की राय सही है कि नगर क्षेत्र का विकास हो और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र की भी विकास हो।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, आप के माध्यम से मैं

कहना चाहता हूं कि रात-दिन नालियों की सफाई कराई गई है।

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : महोदय, मैं अभी अपने क्षेत्र से आ रही हूं। मैंने लोगों की पीड़ा को देखा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहती हूं कि सरकार लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकती हैं, सुविधा नहीं दे सकती हैं, जर्जर सड़कों की मरम्मती नहीं करा सकती हैं, न्यायपालिका के आदेश के वावजूद नालियों की सफाई नहीं करा सकती है तो क्या इस सरकार को, क्या इस राज्य को एक भी पैसा खर्च करने के लिए देनाचाहिए? मैं समझती हूं कि यह सर्वाधिक अनुचित होगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य। आप ज्यादा जल्दी-जल्दी नहीं बोलें। आप अच्छी बात बोल रहीं है। आप थोड़ा-सा धीमा बोलिये।

श्री राधा कृष्ण किशोर : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि ....

अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री राधा कृष्ण किशोर : अध्यक्ष महोदय, जितना जल्दीबाजी में प्रथम अनुपूरक बजट पास कराया जा रहा है उतना ही जल्दीबाज़ी में माननीय सदस्य बोल भी रहीं है।

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : अध्यक्ष महोदय, अब मैं विधि-व्यवस्था के संबंध में कहना चाहती हूं। मैं विधि-व्यवस्था चर्चा सदन में करना चाहती हूं। मेरा क्षेत्र खगड़िया एक संवेदनशील क्षेत्र है। मैं इस के विषय में कहना चाहती हूं। विगत 10 तारीख की बात है। हमारे ख़गड़िया के संसारपुर क्षेत्र में एक ट्रक का अपहरण होता है। अपराधियों के द्वारा एक ट्रक का अपहरण किया जाता है। ट्रक का मालिक सिमरी बखितयारपुर का है। वह वर्षो से लेवी का काम कर रहा है। महोदय, उस ट्रक का अपहरण होता है। ट्रक का मालिक है, उसका भतीजा का, ड्राईवर का, खलासी का और एक ट्रक चीनी का अपहरण होता है। दो दिनों तक अपाराधियों ने अपने पास उन्हें बंधक बनाकर रखा।

वहां, बाजार में आंदोलन किया है इसके लिए लेकिन बार-बार उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जाता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कोई व्यक्ति प्रशासन के पास सुरक्षा के लिए जाता है। थाने बने हैं जनता की सुरक्षा के लिए लेकिन जब जो विवाद लेकर वहां जाते हैं तो उनको प्रताड़ित करने का काम किया जाता है वहां, प्रशासन के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। मैं समझती हूं ऐसी स्थिति में सरकार को पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ शिक्षा का मामला है। माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी बड़ी बातें शिक्षा के बारे में कही हैं। लेकिन मैं कहना चाहती हूं कि हमारे यहां के डी0एस0ई0 महोदय ने अभी पिछले दिनों जो उन्होंने स्थानान्तरण का व्यापार किया, लोगों से पैसा लेकर उनको गृह अंचल में नियुक्त किया गया। एक, महेन्द्र यादव नामक व्यक्ति, जो रोहियार विद्यालय में प्राचार्य बनाया गया, वहां उसका गृह अंचल है, उनका घर वहां है और वे नियुक्त भी वहां हैं। ऐसे सैकड़ों केस हमारे यहां पर हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहती हूं कि एक तरफ जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको दूर-दराज के क्षेत्रों में भेजा जा रहा है एवं पुरूष शिक्षकों पैसा ले कर उनको गृह अंचल में पदस्थापित किया जाता है। मैं समझती हूं कि ऐसी स्थिति में सरकार को पैसा मांगने का कोई अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष : मैं आपकी बात को सपोर्ट करता हूं महिलाओं के संबंध में, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि महिला शिक्षकों को जितनी भी सहूलियत हो सके उनको दिया जाए लेकिन साथ-साथ पढ़ाई के कार्यों में भी कमी नहीं होनी चाहिए।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश को अंगीकार करता हूं। महिला शिक्षिकाओं को पूरा सम्मान देने का काम किया

दो दिनों के बाद जब छूट–कर आते हैं अपराधियों के चंगुल से तो वह थाना जाते हैं अपना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। महोदय, शंभू जायसवाल नामक वह व्यापारी जिसके शरीर को अपराधियों ने सिगरेट से दाग रखा था, जब वह अपनी व्यथा लेकर थाना जाता है तो एफ0आई0आर0 लेने से इंकार करते हैं। संसारपूर मुफस्सिल थाना और मानसी दो थानों के बीच उसको दौड़ाया जाता है। कहां एफ0आई0आर0 दर्ज होता है? उसको थाने में बैठा कर रखा जाता है और कहा जाता है कि 50 हजार रूपया दो नहीं तो 7 ई0सी0 ऐक्ट में केस करेंगें और यह कह कर उस व्यापारी को प्रताड़ित किया जाता है। महोदय, एक तरफ अपराधियों द्वारा अपहरण किया जाता है और दूसरी तरफ थाना के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, 10 तारीख की घटना है और आज 20 तारीख हो गया है और अभी तक उस अपहृत ट्रक का पता नहीं है।

अध्यक्ष : चीनी के संबंध में आपने जो अपहरण शब्द का प्रयोग किया वह सही नहीं है। उस को आप कहिए कि "ले भागा"। चीनी के लिए अपहरण शब्द नहीं कहें।

अध्यक्ष : खाली "अपहरण" शब्द नहीं कहिए, कि चीनी ले भागा।

श्रीमती चन्द्रमुखी : अध्यक्ष महोदय, अपहरण शब्द असंसदीय नहीं है। ट्रक ड्राईवर का अपहरण होता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि पिछले दिनों खगड़िया में एक व्यापारी की हत्या होती है। हमारे यहां के एक व्यापारी अनिल गुप्ता की हत्या होती है और उसके बाद, मैं इसकी सूचना सदन को भी दी थी, अनिल गुप्ता की हत्या के बाद एफ0आई0आर0 दर्ज होता है लेकिन मुख्य अभियुक्त अजय यादव हर जगह खुले–आम घूम रहा है, लोगों को परेशान करता है, मृतक के परिवार को परेशान कर रहा है, लेकिन उसकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वह हर दिन उसके परिवार वालों को धमकाता है और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लोगों ने

जाएगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी। हम तो माननीय सदस्य चन्द्रमुखी जी को भी सम्मान देते हैं लेकिन ये ही अपने अपमान वाली बात को कहती हैं।

श्रीमती चन्द्रमुखी : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहती हूं कि जब सरकार अपना उत्तर देगी तो सरकार की तरफ से उत्तर देने वाले खड़े होकर सरकार की बात को रखेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन बीच में व्यवधान उत्पन्न करवान को प्रयत्न न किया जाए। मैं जो कह रही हूं उसको ध्यान पूर्वक सुना जाए।

अध्यक्ष महोदय, आज से कुछ दिनों पूर्व जब सदन में चर्चा चल रही थी, सदन में बहस चल रही थी तो बहुत से आंकड़े दिए जा रहे थे। बार-बार उत्तर प्रदेश की चर्चा, महाराष्ट्र एवं गुजरात की चर्चा लोग कर रहे थे। मैं कहना चाहती हूं मेरे पास भी आंकड़े है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास भी उत्तर प्रदेश के आंकड़े हैं। मैं यह बताना चाहती हूं, पता नहीं माननीय मंत्री महोदय को यह पता है या नहीं या सत्तर पक्ष के विधायकों को पता है या नहीं, मै उनका ध्यान इन समाचारों के तरफ दिलाना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है, यह सरकार जिस समय से वहां है, वहां पिछले 21 वर्षो से जो सिया और सुन्नियों के झगड़े चले आ रहे थे उसका निपटारा इस सरकार ने करवाया। पिछले 21 वर्षो से वहां सिया औरसुन्नी के झगड़े चले आ रहे थे जिसकी बजह से उनका जुलुस नहीं निकलता था, वहां पर कल्याण सिंह जी की सरकार ने 21 वर्षो के पश्चात् इस झगड़े को सुलझाया और अब वहां उनका जुलुस निकालने लगा है। यह काम वहां हमारी पार्टी की सरकार ने किया हैं। यहां पर जो वहां के अपराध का आंकड़ा दिया गया, उत्तर प्रदेश की चर्चा की गयी, उत्तर प्रदेश के बारे में कहा गया। मेरे पास इस समय उत्तर प्रदेश का आंकड़ा तो उपलबध नहीं है लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मुलायम सिंह यादव जी जब वहां के मुख्य मंत्री थे.........

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या को

शायद पता होगा कि उत्तर प्रदेश में आज तमाम प्राईमरी सकूल के शिक्षक हड़ताल पर हैं, स्कूल बंद हैं। पता नहीं माननीय सदस्य चन्द्रमुखी जी को पता है या नहीं।

श्रीमती चन्द्रमुखी : अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मंत्री महोदय से अधिक वहां की जानकारी है। वहां ऐसी कोई बात नहीं है। वहां से मैं चल कर यहां आयी हूं।

श्री जयप्रकाशनाराण यादव : अध्यक्ष महोदय, तमाम दूर-दर्शन एवं रेडियो से लेकर समाचार में आ रहा है कि वहां दो महीने से प्राईमरी स्कूल बंद हैं।

श्री चन्द्रमुखी देवी : अध्यक्ष महोदय, अगर वाद-विवाद या शास्त्रार्थ मेरे और माननीय शिक्षा मंत्री जी के बीच में होना है तो यह परम्परा आप प्रारम्भ कराइये, हम शस्त्रार्थ करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र का जहाँ तक सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में सारी सरकार चिंतित है कि शिक्षा की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, महिलाओं के शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन सरकार क्या इस विषय पर एक शब्द भी बोल सकती है? महोदय, एक तरफ लोक-सभा के अन्दर महिला आरक्षण बिल जब आता है, वहाँ पर जब महिलाओं के लिये विधान-सभा और लोक-सभा के अन्दर आरक्षण का बिल हुआ तो एक सहमति बन सकती थी लेकिन होता क्या है? महोदय, अभी तक इस प्रदेश में या देश के अन्दर महिलाओं को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका है। पुरूषों को तो विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण मिला लेकिन इस बिल के माध्यम से पहली बार महिलाओं को आरक्षण देने का प्रयत्न हमारी केन्द्र की सरकार ने किया तो इनलोगों ने क्या किया?

अध्यक्ष : असल में वे लोग क्या सोचते हैं, वे कहते हैं महिलाओं के बारे में कि-

वर्ण व्यवस्था में महिलायें भी हैं। हजारों साल से प्रताड़ित दलित-पिछड़ी जाति की महिलाओं को जबतक सम्मान नहीं मिलेगा जबतक उनके सम्मान के लिये माननीय लालू प्रसाद और मुलायम सिंह जी लड़ाई लड़ते रहेंगे। महोदय, हमलोग यह लड़ाई पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक लड़ते रहेंगे और पिछड़ी जाति के महिलाओं को उनका हक और सम्मान दिलाकर रहेंगे।

अध्यक्ष : मंत्री जी को शायद मालूम होगा, यहाँ जो आरक्षण बिल पास हुआ है, मैं इनको कहूँगा कि उसको जरा देख लीजिएगा, वह तो और भी बहुत क्रांतिकारी है, इनकी शायद याद नहीं होगा, उन्होंने ही पास किया है। पहले आरक्षण हरिजन की महिला को, तब आरक्षण आदिवासी महिलाओं को, तब आरक्षण अत्यंत-पिछड़ी जाती के महिलाओं को, तब आरक्षण पिछड़ी जाति के महिलाओं को और तब उसके बाद आरक्षण उनको जो बड़े-बड़े महलों में निवास करते हैं।

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : अध्यक्ष महोदय, यह विषय ....

(व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश लाल : अध्यक्ष महोदय, आप हमलोगों की तरफ नहीं देखते हैं, सिर्फ उधर ही देख रहे हैं।

अध्यक्ष : वे बोल रही हैं इसलिए मैं उनकी तरफ बोल रहा हूँ। आप तो बीच-बीच में ऐसे ही खड़े हो जाते हैं, इसलिए आपकी तरफ दृष्टि कम करते हैं।

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : अध्यक्ष महोदय, आरक्षण का जो प्रावधान है, उसके बारे में आपकी जानकारी है लेकिन शायद मंत्री महोदय को जानकारी नही है इसलिए वे एक-एक शब्द पर खड़े हो रहे हैं।

महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि हमलोग विषम परिस्थिति से गुजर रहे

"त्वं वैष्णवी शक्ति अनन्तवीर्या,
विश्वश्व बीजम् परमासी माया,
सम्माहितम् देवी समस्त येतल
त्वं प्रसन्ना भूवि मुक्त हेतुः।"

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : अध्यक्ष महोदय, यह वर्षों की परम्परा रही है, इस देश की परम्परा रही है कि महिला को देवी के रूप में प्रतिष्ठापित करके बिठा दो ताकि वह किसी विषय पर बोल नहीं सके। लेकिन आज के दिन मैं कहती हूँ कि महिला को कोई देवी बनाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। नारी है तो उसको नारी के रूप में सम्मान मिलना चाहिए। अगर यह आप कर पाते हैं तो मैं सतझती हूँ कि यह एक बहूत बड़ी उपलब्धि होगी।

महोदय, आरक्षण बिल आ रहा था महिलाओं के लिये, उनके लिये आरक्षण होने देना चाहिए था। लेकिन इनलोगों वैसा होने नहीं दिया। इनलोगों ने वहां पर ज़ा उत्पात मचाया, उसके बारे में मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहती हूँ। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के बीच में इनलोगों ने विष-वमन करने का काम किया। इनलोगों ने महिलाओं के बीच में बँटवारा करने की कोशिश की, महिलाओं के बीच में विभेद पैदा करने का काम किया। महोदय, महिलाओं को पिछड़ा माना गया इसलिए उनको आरक्षण देने के लिये केन्द्र सरकार उनको आरक्षण देना चाहती थी। लेकिन इनलोगों ने महिलाओं के बीच में भेद पैदा किया, महिलाओं को अगड़ी-पिछड़ी, विभिन्न जाति-धर्मों के आधार पर बाँटने की कोशिश की। महोदय, यह बहुत बड़ा षडयंत्र है इस देश के साथ, इस देश की महिलाओं के साथ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। महोदय, इसको रोकने का प्रयत्न होना चाहिए था।

(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव : महोदय, इस देश में वर्ण व्यवस्था है और

हैं आज पूरे देश की निगाहें बिहार प्रदेश की तरफ लगी हुई है। आज पूरे बिहार प्रदेश की बराबर देश में चर्चा हो रही है। आज बिहार प्रदेश की स्थिति ऐसी बनी है कि धारा 356 का उपयोग होना चाहिए। महोदय, ऐसी परिस्थिति में जब पूरे देश की दृष्टि बिहार प्रदेश पर लगी है तो मैं कहना चाहती हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी से और जितने भी मंत्रिमंडल के मंत्रीगण हैं, सत्ता-पक्ष में बैठे हुए जो विधायक लोग हैं, उनको संयत होना चाहिए ताकि यह संदेश न जा सके कि इनके आचरण के कारण धारा 356 को उपयोग हुआ? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ, आज इस सदन में हमलोग बैठे हैं, गम्भीर विषय पर चर्चा करने के लिए हमलोग आज यहाँ बैठे हैं। महोदय, आज बरसात का समय आ गया ....

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप थोड़ा-सा संक्षेप में अपनी बात कीजिए।

(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रमुंखी देवी : माननीय मंत्री जी, अभी आपलोगों की रैली होने वाली है। रैली में आप भाषण दीजिएगा, यहाँ पर इस सदन में हमें अपनी बातों को कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय, आज जो स्थिति है अभी, इसपर विचार करना चाहिए। इन्होंने कहा कि जब धारा-356 का प्रयोग होगा तो हमारी संख्या घटकर 55 हो जायेगी। हमको इसको चिन्ता नहीं है क्योंकि अगर बिहार प्रदेश को सुरक्षित देखना चाहते हैं, हमारी चिन्ता पूरे प्रदेश के लिए है, हमारी चिन्ता किसी पार्टी के लिए नहीं है, हमारी चिन्ता अपने प्रदेश को बचाने के लिए है। महोदय, मैं आज के दिन के लिए कहना चाहती हूँ कि इस सदन के अन्दर जब हम बैठते हैं, बाहर जब अपनी पार्टी के विषय में बहुत सारी चर्चा करते हैं लेकिन सदन के अन्दर जब हम बैठते हैं तो विभिन्न विषयों पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए और हर व्यक्ति को चाहिए चाहे सत्ता पक्ष में बैठता हो या विपक्ष में बैठता हो कभी अपने गिरोबान में झांकर देखना चाहिए कि

इन विषयों को लेकर जब वह बाहर में जायेगा तो लोगों के बीच अपनी बात कैसे रखेगा।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य राधाकृष्ण किशोर जी।

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दिया जाय। मुझे कनकलुड करने दीजिए।

अध्यक्ष : ठीक है। आप बोलिए।

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में संभवतः अंतिम दिन बहस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि चिकित्सा व्यवस्था की चर्चा पिछली बार मैंने की थी और मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया था । आज पूरे राज्य में इस विषय को लेकर परेशान है, जगह-जगह गाँव में क्योंकि बरसात का समय है, जगह-जगह लोगों के छोटे-छोटे बच्च, गरीबों के बच्चे, दलितों के बच्चे को कुत्ते काट रहे हैं लेकिन कुत्ते काटने की दवा किसी अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। मैंने महत्वपूर्ण सवाल इस सदन में उठाया था लेकिन उसे आने नहीं दिया। आज की आवश्यकता नहीं है कि जो गरीब जिनके बच्चे को कुत्ते काट रहे हैं, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए? पिछली बार इस प्रश्न को इस सदन में एक बार उठाया गया तो यही सत्ता पक्ष की तरफ से उत्तर आया था कि कुत्ते को मार देंगे। हम कुत्ते को मार देंगे लेकिन कुत्ते काटने के बाद जो इंजेक्सन लगाया जाता है, उसकी व्यवस्था नहीं की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूं कि यह सरकार संवेदनहीन है, ये गरीबों, दलितों के विषय में सोचती नहीं है केवल नारेबाजी करती है। इसलिए सरकार को किसी भी विषय में, किसी भी विभाग पर एक नया पैसा नहीं देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि जो सरकार केवल घोषणायें करे, घोषणायें की पूर्त्ति नहीं करे, समस्याओं का निदान नहीं कर

केवल आश्वासनों को लम्बित रखे, विधान-सभा में प्रश्नों का उत्तर देने से कतराये इसलिए इस सरकार को एक नया पैसा नहीं देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस सरकार को एक नया पैसा नहीं देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : दोनों पक्ष की कोई बात प्रोसिडिंग में नहीं जायेगी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग बैठिये। अब उनको बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये, आप बोलिये।

श्री राधा कृष्ण किशोर : अध्यक्ष महोदय, प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी के संदर्भ में जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं.........

(व्यवधान)

मैं उसके संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं (व्यवधान).... महोदय,.........

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये। बैठिये। (व्यवधान जारी) आप बैठिये न।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : बैठिये मुंशी बाबू, बैठिये।

(इस अवसर पर मा0स0 मुंशी लाल राय अपनी सीट पर बैठ गए)

श्री राधा कृष्ण किशोर : महोदय, बिहार सम्पूर्ण राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण राज्य है।

(व्यवधान जारी)

महोदय, बिहार की जो संस्कृति रही है, बिहार के पास जो संपदाएं हैं यह सारे राष्ट्र के दूसरे राज्यों में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन आज इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आजादी के पचास वर्षों के उपरान्त बिहार राज्य को देश के मानचित्र में जिस स्थान पर हाना चाहिए था, उस स्थान पर हमारा राज्य नहीं है।

महोदय, आजादी के पचास वर्षो के दरम्यान बिहार में जो सामाजिक संस्कृति पैदा होनी चाहिए थी, जो आर्थिक संस्कृति पैदा होनी चाहिए थी, न तो वह संस्कृति पैदा हुई और इस राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि यहां के लोगों के बीच जो सोशल, जो समाजिक संतुलन होना चाहिए, जो आर्थिक संतुलन होना चाहिए, वह आजादी के पचास वर्षो के उपरानत भी नहीं हो पाया है। और यही कारण है कि जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी हैं.........

अध्यक्ष : माननीय सदस्य राधा कृष्ण किशोर जी, हमारी जो पुरानी संस्कृति थी वह वेद से निकली हुई थी, वह संस्कृति तो अभी जरा धूमिल पड़ गई लेकिन कोई संस्कृति तो निकली है और अगर अच्छा नाम दे सकिये तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अभी जो संस्कृति निकली है नयी, वह मारूति संस्कृति है और उसका जो प्रभाव है...

श्री राधा कृष्ण किशोर : महोदय, मैं इसी की चर्चा करना चाह रहा था।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य हिन्दी केशरी जी, कुछ अच्छी बात बोलिये, कुछ अच्छी बात कहिये।

(व्यवधान)

श्री राधा कृष्ण किशोर : हिन्दी केशरी जी, मैं आपके कहने से बैठ जाऊंगा या आसन के कहने से बोलूंगा?

(व्यवधान)

महोदय, मैं व्यक्तिगत् रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं कि यद्यपि कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न चरणों में यह राज्य सरकार जहां विफल रही है, वहां एक बात को मैं व्यक्तिगत् रूप से स्वीकार करता हूं कि बिहार में जो सामाजिक संतुलन, सामाजिक चेतना जगाने का काम लालूजी ने किया है, यह बिहार के इतिहास में स्मरणीय होगा, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं।

महोदय, अभी महिला आरक्षण के मुददे पर पार्लियमेन्ट में जिन भावनाओं से अवगत कराया राष्ट्र को, यह सिर्फ सारे हिन्दुस्तान के लिये ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे स्थालों के लिये एक पैगाम है। मैं इस बात को बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि, मैं जानता हूं, बिहार में जितने भी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं और उस में जो सेविकायें कार्यरत हैं, क्या आप बता सकते हैं कि सेविका के पद पर समाज के किस स्तर की महिलायें पदस्थापित हैं। समाज के जो 70 प्रतिशत जो दलित, पिछड़े दबे कुचले लोग हैं, अगर आरक्षण की बात की जायेगी तो उनकी बात की जायेगी। जब उनको सेविका का पद नहीं मिल पाता है तो पार्लीयमेन्ट का सीट कैसे मिल पायेगा। हमारी पार्टी सत्ता पार्टी को समर्थन दे रही है उनके कार्यो से प्रेरित होकर। आजादी के 50 वर्षों के बाद, आर्थिक रूप से समाजिक रूप से जो पीछे रह गये हैं, जो छूट गये हैं, हमारा फर्ज बनता है कि समाज में उनको एक स्थान दें। डेमेक्रेटिक गर्भनमेन्ट में सरकार का यह कर्त्तव्य बनता है कि अपने स्टेट के लोगों को, अपनी जनता और सभी धर्म के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करे, जिसमें वह गभरनेन्स करता है उस टेरीटोरी को आगे बढ़ाने का काम

करे। आपने समाजिक चेतना पैदा की, जो दबे, कुचले लोग हैं उनको राजनीति चेतना दी, उनको समाजिक चेतना दी, उनमें राजनीतिक चेतना आ गयी, समाजिक चेतना आ गयी और डेभलपमेंट 8 वर्षो में हो गया। सिर्फ राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना को एकोनामिकल प्लेटफार्म पर कैसे खड़ा करना चाहते हैं। यह सदन इस बात की गवाह है कि उन गरीबों, दलितों और पिछड़ों के उत्थान के लिये आपने कार्यक्रम चलाये। केन्द्र सरकार से जो स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के तहत जो राशि मिली जिसमें आपने अपना राज्यंश भी दिया, इस राशि का उपयोग सही तरीके से हुआ या नहीं, इसको आपने देखा या नहीं?

जिस राशि को केन्द्र सरकार ने हरिजनों के उत्थान के लिये दिया, आपने भी अपना राज्यंश दिया, वह हरिजनों के उत्थान के लिये उपयोग हुआ या नहीं। इस से बड़ा एकोनोमिकल आफेन्स हो सकता है क्या? कि आजावनी नाम की संस्था ने रिलाएंस और टाइमेक्स नाम की कम्पनीयों का शेयर खरीदा गया। हम दलितों और पिछड़ों के विकास की बात करते हैं, यह सरकार दलितों के बार में बात करती है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : माननीय सदस्य श्री राधा कृष्ण किशोर सिरियस बात कह रहे हैं इसको सरकार नोट करे 10 करोड़ रूपया चला गया शेयर की खरीदारी में। उसे खास तौर परयोजना मंत्री स्पष्ट करें।

अध्यक्ष : न वह शेयर वाले का पैसा है, न हमारा और आपका पैसा है, यहां जो पैसा आता है और यहां हम और आप जो बैठे हुये हैं वह गरीबों का पैसा है, मैं पुनः दोहराता हूं कि महुआ की रोटी पर जो नमक रखकर खाता है, उस नमक के टैक्स का पैसा है, उसके सही उपयोग और सद्व्यवहार गरीबों के कल्याण के लिये होना चाहिये।

महोदय, मैं विशेषकर आपके माध्यम से बिहार की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। आप महिला हैं, यह

बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार के इतने महत्वपूर्ण पद पर आज एक महिला विराजमान है और आपके अन्दर संवेदनशीलता है। यद्यपि मैं यह जानता हूँ कि आप राजनीतिक परिवार से आयी हैं लेकिन जो सूझबूझ होनी चाहिए, हो सकता है कि उसमें कुछ आपमें हो, लेकिन इन्सान अनुभव से ही आगे बढ़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप इन बातों को समझेंगी तो निश्चित रूप से उन बातों को क्रियान्वित करने की ओर काम करेंगे। महोदय, पौष्टिक आहार बिहार के 69 आँगनबाड़ी केन्द्रों से राज्य सरकार एक वर्ष से लेकर छह वर्ष के बच्चों के बीच वितरित करती है। बिहार सरकार की एक संस्था है ड्रग लेवोरेटरीज और उसके डिप्टी डाइरेक्टर ने लिखा है गवर्नमेन्ट को कि यह जो रेडी टू ईट फूड है वह ह्यूमन कन्जम्पशन के लिए फिट नहीं है, वह खाने के लिए उचित नहीं है, वह उपयुक्त नहीं है। महोदय, 85 करोड़ की लागत से आप पोषाहार के लिए खरीदते हैं और उसको एक से छह वर्प के बच्चों के बीच, दलित, शोषित, पिछड़े और गरीब बच्चों के बीच उसको वितरित करते हैं और इसके बारे में यह है कि यह खाद्यान्न उपयोग के लायक़ नहीं हैं, फिर भी उनका वितरण आप उन बच्चों के बीच कर रहे हैं। आप इसके सम्बन्ध में अपने जवाब के क्रम में कहियेगा और मैं जो कह रहा हूँ और आप जो कहेंगे उसमें अगर कोई विभेद होगा तो उसके लिए जाँच ही एकमात्र उपाय हो सकती है।

माननीय मुख्यमंत्री जी, अनुपूरक बजट तो सभी विभागों का लिया जा रहा है 4 महीने के लिए, लेकिन इसमें एक है माँग संख्या-4 में मंत्रिपरिषद्। महोदय, लोकतांत्रिक सरकार का पहला कर्त्तव्य होना चाहिए कि राज्य की राशि को कम से कम खर्च करें भौतिक विषयों पर, जो आरामदेह चीजों से सम्बन्धित खर्चे हैं, उनपर कम-से-कम खर्च होना चाहिए क्योंकि वह राशि जनता की गाढ़ी कमीई होती है। मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि आपको अपने मंत्रियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आज आपकी राशि, जो

खजाने में पहुँचती है, उस राशि का 80 प्रतिशत गरीबों के लिए योजनाओं पर खर्च नहीं हो रहा है। उस राशि का 80 प्रतिशत आज गैर-राजस्व व्यय पर खर्च हो रहा है, नन-रेभेन्यू एक्सपेन्डीचर में व्यय हो रहा है, गैर योजना मद में वेतन पर, यात्रा भत्ता पर, राजकीय भोज पर, मंत्रियों की सुख-सुविधाओं आदि पर व्यय हो रहा है। आप संवेदनशील हैं, इसलिए यह बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इस बात का ख्याल कीजिये कि जो अधिक से अधिक राशि खर्च हो रही है वह गरीबों के कल्याण के लिए खर्च हो, वह इस राज्य की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य राधाकृष्ण किशोर जी, आप एक सेन्टेन्स में क्यों नहीं कहते हैं कि जो टॉप हेवी इक्सपेन्डीचर है और जो वेस्टफुल एक्सपेन्डीचर है, उसपर कर्ब होना चाहिए।

श्री राधा कृष्ण किशोर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप बाहर निकलिये जरा यहां से पटना में और देखिये, हार्डिंग पार्क को छोड़ दीजिये, सर्पेन्टाइन रोड को और बेली रोड को छोड़ दीजिये, माननीय मोदी जी सदन में नहीं उस सम्बन्ध को उन्होंने माना या नहीं, ...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपनी बातों को संक्षिप्त कीजिये।

श्री राधाकृष्ण किशोर : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन मिनट में अपनी बातों को समाप्त कर दूँगा, मैं बहुत आँकड़े देकर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत भावनात्मक बात कहना चाहता हूँ, माननीय मोदी जी ने जो सम्बन्ध बताया, वे उसको मानें या नहीं लेकिन मैं राधाकृष्ण किशोर एक भाई के नाते अपनी बहन से कह रहा हूँ कि आप तीन-चार सड़कों को छोड़ दीजिये तो पटना में और कोई भी सड़क चलने के लाचक नहीं है। आप जाकर देखिये, चाहे दीघा चले आइये, नाला रोड चले जाइये, कंकड़बाग़ चले जाइये, फुलवारी चले जाइये, कहीं भी चले जाइये, सड़कों की हालत अत्यन्त दयनीय है। महोदय,

यह बिहार की राजधानी है और ऐतिहासिक राजधानी है जो पाटलिपुत्र के नाम से जानी जाती थी और यहां सड़कों की स्थिति ऐसी है कि एक भी सड़क पर नहीं चल सकते हैं।

महोदय, राजधानी की सड़कों की यह स्थिति हो सकती है। जिला मुख्यालय से राजधानी मुख्यालय में आने वाली सड़कों की क्या स्थिति हो गई। यह वही राज्य है जहां पी0डब्लू0डी0 की चार हजार किलोमीटर सड़कें दुर्व्यवस्था में हैं। महोदय, आज यह स्थिति है कि आप वहां नहीं जा सकते। माननीय सदस्य श्री ओ0पी0 लाल जी ने जी0टी0 रोड के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट किया है। मैं वह भी इसमें जोड़ना चाहता हूं। यह स्थिति आप पूरे राज्य का है। महोदय, एक देश की जनता को आज क्या चाहिए। मकान, कम्यूनिवेशन एजेकेशन, शुद्ध पीने का पानी और हेल्थ की अच्छी व्यवस्था। माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम स्वास्थ्य में भी पिछड़े हुए हैं। महोदय, आज तो मैं नही ला पाया लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि उड़िसा जो सबसे पिछड़ा हुआ राज्य था, बिहार से भी काफी पिछड़ा हुआ था महोदय, जिन बातों की मैं चर्चा कर रहा हूं एजूकेशन, कम्यूनिवेशन, स्वास्थ्य, शुद्ध पीने का पानी इस सब में उड़िसा आज हम से आगे है, बिहार राज्य से आगे है। माननीय मुख्यमंत्री जी मैने बताया था कि 10 करोड़ जनता गरीब हैं जिसमें 5 करोड़ 60 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। आपको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर के बारे में राज्य में 70 प्रतिशत लोगों को आज भी शुद्ध पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा है। इन सब मामलों की ओर आपको देखना होगा और यह एक बहुत बड़ी समस्या इस राज्य के लिये हैं। आप इन सब बातों से निकलिये कि कौन कहां 356 लगाता है और कौन कहां जाता है। ये राजनीतिक बातें है, राजनीतिक खेल होती रहेगी। सरकार को जनता के बीच में आगे बढ़कर काम करना चाहिए। आज आगे बढ़कर काम करियेगा तो जनता आपके साथ है, आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता। आज यही स्थिति ड्रिंकिंग वाटर के बारे में है।

महोदय, आज सबसे बुरी स्थिति बिहार के छोटानागपूर क्षेत्र का है। आपने वहां पर कानून व्यवस्था से निपटने के लिये पारा गिलिटरी फोर्स बुलाया। मैं और माननीय सदस्य श्री संकटेशवर सिंह जी शुक्रवार को वहां गये थें। इनके कंस्टीच्येंसी में सी0आर0पी0एफ0 ने एक पैसे व्यक्ति की निमर्म हत्था कर दी......

अध्यक्ष : मैं उनको बोलवा रहा हूं। उन्होंने कहा है।

श्री राधा कृष्ण किशोर : महोदय, इसलिए मैं इस मामले में संवेदनशील होना चाह रहा था। छोटानागपुर, संथाल परगना जहां इतनी समस्याओं से घिरा हुआ है तो इन समस्याओं की ओर भी सरकार को चिन्तित होना पड़ेगा और देखना होगा कि इसका कल्याण कैसे हो सकता है। महोदय, मैं फिर कहना चाहता हूं कि बिहार को आगे ले जाने के लिये आठ वर्षो में क्या प्रयास हुआ। आपके पास सारी संभावनायें प्रबल हैं। जितनी मात्रा में खनीज सम्पदायें छोटानागपुर, संथाल परगना में मौजूद हैं उस स्थिति में वहां प्रगति नहीं हो पा रही है। जापान ने कहा था कि हिन्दुस्तान का बिहार अगर मुझे मिल जाये तो मैं सात जापान खड़ा कर सकता हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अपनी बात समाप्त करते हुए कि आप अपने मंत्रियों से पूछिये, यहां डेमोक्रेसी है, हमारा कर्त्तव्य होता है, सरकार का कर्त्तव्य होता है कि अपने राज्य की जनता को आगे बढ़ाने में पहल करे। आप अपने मंत्रियों से पूछिये कि वह पटना मुख्यालय छोड़कर ओर अपने कंस्टीच्वेंशी को छोड़कर, कितने ऐसे मंत्री हैं जो 20 सूत्री कार्यक्रम के वाबजूद दूसरे जिले का भ्रमण करते हैं। इतनी बड़ी समस्या से यह राज्य गुजर रहा है और ....

आपके सारे मंत्री हेडक्वाटर में पड़े रहते हैं। महोदय, केन्द्र सरकार में दिल्ली में जो कार्य की संस्कृति है उसके अनुसार केन्द्र सरकार के सारे पदधिकारी/कर्मचारी ८ बजे सुबह घर से निकलते हैं और कार्यालय का कार्य करने के बाद ८ बजे रात्रि में ही घर पहुंचते हैं। लेकिन पटना सचिवालय में

आपके पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यालयों में ११:३० बजे पूर्वाह्न के पहले नहीं पहूंचते और ४:३० बजे अपराह्न में ही कार्यालय छोड़ देते हैं। इसलिये उसकार को अपने पदाधिकारियों और कर्मचारियों पर नियंत्रण होना चाहिये नहीं तो मैं समझता हूं कि बिहार का विकास नहीं हो सकता है। साथ ही महोदय पदाधिकारियों का बिहेवियर भी ठीक नहीं रहता है। आज भी पदाधिकारियों के दिमाग में यह बात बैठी हुयी है कि वे ब्रिटिशकाल के पदाधिाकारी हैं। अंत में अपनी बात दोहरा तो हुये मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि आप अपने पदाधिकारियों पर नियंत्रण करें और जो भी पदाधिकारी हैं वे निश्चित रूप से साढ़े दस बजे कार्यालय में उपस्थित रहें और आम जनता के कार्यों को करें और उनकी बातों को सुनें। इन्हीं शब्दों के साथ में अध्यक्ष महोदय, आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया धन्यवाद।

श्री संकटेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत है-

"केकर केकर धरूं नाम, कमरी ओढ़ले सउसे गाँव।"

महोदय, किस विभाग से प्रारंभ करें? किस विभाग की स्थिति सहि मानें? सबकी स्थिति वही हैं। सबसे पहले आप विधि व्यवस्था की ही बात ले लें। परसों मैं गया था पलामू। वहां की पटना के संबंध में एक एडजर्ममेंट मोशन भी आपको दिया था जिसमें कहा गया था कि पलामू जिलन्तर्गत पांकी थाने के सीकन ग्राम निवासी श्री पारसनाथ सिंह को श्री रामकृष्ण असिस्टेंट कमाण्डेंट ने सी आर0पी0एफ0 के जवानों के साथ, दिनांक १८ जुलाई, ९८ को सुबह करीब ९ बजे निरपराध गिरफ्तार कर लिया। थाना लाकर लगातार उसकी क्रूर एवं निमर्म पिटाई की गई। वह बराबर अपने को निर्दोष बताता रहा एवं सच्चई भी है कि आजतक न तो उस व्यक्ति के विरूध कोई अपराधिक मामला दर्ज हुआ है और न ही आम जानकारी में उसका कोई अपराधिक इतिहास रहा है। घोर अमानवीय प्रताड़ना के कारण उसकी मृत्यु

थानें में ही हो गई। तत्पश्चात स्थानीय डाक्टरों पर दबाव डालकर झूठा प्रमाण पत्र भी बनवाने का असफल प्रयास किया गया। इस पटना से संपूर्ण इलाके में जन मानस भयाक्रांत है।

महोदय, यह स्थिति बनी हुयी है विधि व्यवस्था की इस राज्य में। महोदय इस संबंध में मैं चाहूंगा कि आप भी वहां से रिपोर्ट मंला लें। हमने मांग कर रखा है कि इसकी न्यायिक जांच हो। हमारी यह भी मांग है कि मृतक के परिवार को मुआवजा दिया जाय। उसके आश्रित परिवार के सदस्य को नौकरी दी जाय। नाबालिग बच्चे की पढ़ाई की व्यवस्था की जाय।

महोदय, विधि व्यवस्था कहां है? महोदय, मैं आपके समक्ष अपनी बात रख रहा था और संसदीय कार्य मंत्री वहां बैठे हुये थे और वे कह रहे थे कि यह तो हमारे नियंत्रण से बाहर की बात है।

श्री रामश्रय प्र० सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं प्वाइंट औफ इनफारमेशन पर हूं। महोदय, मुझे भी माननीय सदस्य, श्री संकटेश्वर सिंह ने सारी बातें बातायी। हमने भी एक घंटा पहले पलामू के एस0पी0 से बातें की है। एस0पी0 ने स्वीकार किया कि सी0आर0पी0एफ0 के लोगों ने श्री पारसनाथ सिंह की हत्या की और वे केस फाइल कर रहे हैं। महोदय, यह सिरियस बात है पुलिस ने उस लड़के को पीट कर मार डाला। यह जरूरी है कि वहां के एस0पी0 ने अच्छा काम किया उन पर एफ0आई0आर0 करवाया और आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं। महोदय, यह चिंता की बात है कितनी ब़रबरता बढ़ गयी है पुलिस की यह इस बात का घोतक है। और मैं मुख्यमंत्री को जेहन में इस बात को लाना चाहता हूं। माननीय सदस्य, श्री संकटेश्वर बाबू ठीक ही बता रहे थे महोदय उसके लिये कम्पनसेशन और आगे क्या बात होनी चाहिये तभी संकटेश्वर बाबू के इलाके में शांति हो सकेगी महोदय। महोदय, पलामू उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। अगर पुलिस इस तरह बर्बरता में आ जाएगी तो कोई सुरक्षित हो सकेगा? मैं यही ऐड करना चाहता था महोदय।

श्री उपेन्द्र प्र० वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य कह रहे थे मैंने कहा कि सी0आर0पी0 भारत सरकार के अंडर में होता है लेकिन कानून और व्यवस्था का उल्लघंन करते हैं वह हमारी चीजे है। रामाश्रय बाबू ने जिन बातों को उठाया है उसको देखेंगे और कार्रवाई करेंगे।

श्री संक्टेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, विधि व्यवस्था की जो स्थिति है, एक उदाहरण से आप समझ गये होंगे कि बिहार की स्थिति क्या हो गई है। हमारा क्षेत्र पूरा उग्रवादी है, पूरा जो पलामू जिला है इसके बारे में आप जानते होंगे, लेकिन तत्कालीन सी0आई0डी0 डी0आई0जी0 मिस्टर कैरें ने वर्ष १९८७-८८ में बिहार सरकार को लिखा या और बिहार सरकार ने भारत सरकार को लिखा था कि औरंगाबाद और गया में चल उग्रवाद पलामू की आर बढ़ रहा है, और जब यह पलामू में चला जायेगा तो उधर इतना वे सुरक्षित होंगे कि वह आपके लिये सरदर्द हो जोयगा, लेकिन भारत सरकार इस पर कुछ सोचा नहीं और आज भी सोच नहीं पा रही है। ऐसी स्थिति पैदा हो गई हैं विधि-व्यवस्था की आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिये, वहां लोग किस हालत मे जिन्दा रह रहे है और हम और आप उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं- स्थिति ऐंसी बनी हुई है। मैं जिस इलाके की बात कह रहा हूं, उस इलाके के कम से कम ५०० लड़के सूरत, पंजाब, काश्मीर भागे हुये हैं, यह सोचकर कि यहां रहेंगे तो जान से मारे जायेंगे- तो कहां जायेगा आज प्रशासन? उग्रवादियों से बढ़कर पुलिस प्रशदसन उग्रवाद हो गाया।

अब मैं आपका ध्यान महोदय, दूसरी ओर, शिक्षा की ओर ले जाना चाहता हूँ, अभी हमारे शिक्षा मंत्री श्री जयप्रकाश नारायण यादव नहीं हैं, वे सदन से चले गये हैं, शिक्षा तो समझिये बिहार में परीक्षण केन्द्र हो गया हैं। परीक्षण केन्द्र बना हुआ है- कभी इंगलिश लाओ, कभी इंगलिश हटाओ, कभी टेन प्लस टू तो कभी टू प्लस टेन- ऐसी स्थिति हो गई कि आज शिक्षा हमारे यहां परीक्षण (एक्सपेरिमेंट) का केन्द्र बनती हुई है, इसके चलते पढ़ाई

बिल्कुल ही समाप्त हो गई है। हाई स्कूल में जहां १४-१४ शिक्षक रहते थे आज वहा मात्र दो हैं और दोनो एक ही सब्जेक्ट के, एक ही बिषय के हैं। मध्य विद्यालयों के शिक्षकों का जो स्थानान्तरण हुआ, उसका नतीजा यह है कि हमारे क्षेत्र के १७ मध्य विद्यालय बंद हैं, आखिर कैसे चलेगा ये विद्यालय? अध्यक्ष महोदय, सामने, आपके आपके चैम्बर में बातें हुई थीं कि कम से कम स्थानान्तरित जो हुये हैं, उसको आप रिटर्न कर दें तो ८० प्रतिशत प्रोब्लम आप सौल्भ कर देंगे, माननीय शिक्षा मंत्री ने इसके इक्सेप्ट भी किया था, हमारे तत्कालीन मुख्य मंत्री एक-दो जगहआम सभा में भाषण भी दिया था कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका है। आखिर आप कहां सोच रहे है, क्या कर रहे हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह जो ग्रामीण विकास विभाम है, ग्रामीण विकास के जो कार्य हैं अध्यक्ष महोदय, जैसा इस विभाग का कार्य है उसी से सरकार की प्रतिष्ठा बची हुई है। लेकिन इसका पैसा कहां जा रहा है? जिस जगह की आप बात करते हैं, हरिजन, आदिवासी की बात करते हैं, आपको मालूम होना चाहिये ३५-३५ करोड़ रूपया सरेन्डर हुआ है, आप इस बारे में सोंच लीजिये।

अब मैं लोक स्वा0 अभियत्रणा विभाग की बात करता हूँ, पी0एच0ई0डी0 में आपको काफी मदद मिली है, शुद्ध पेय जल देने की बात है, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि वर्ष ८८-८९ में जल मिनार बनाकर पानी आपूर्त्ति की बात हुई, पाईप भेजे गये, बाद में काम बंद हो गये, वर्ष १९९५ में मैंने सवाल उठाया, तत्कालीन मंत्री ने आश्वासन दिया कि सितम्बर, ९५ से कार्य प्रारंभ करा दिया जायेगा, इसके लिये माननीय मंत्री ने ७ लाख रूपया दिया भी, लेकिन वह सी0डी0 में जमा हो गया, साढ़े चार लाख रूपया सरेन्डर हो गया, मैं इस संबंध में बराबर कह रहा हूँ, छोटानागपुर की बात है, लेकिन अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ। बाचरिंग कराये हुये ढाई वर्ष हो गये, डेढ वर्ष हो गये, जैसे पांकी में १८, मनातू में - ११, लेसलीगंज में - १७

बोरिंग हो गये, लेकिन अभी तक लोअरिंग नहीं हुआ है, मैने जब मंत्री जी से कहा कि इसके लिये पाईप दिया जाय तो वे बोले कि भेज दिये हैं, तो वह पाईप कहां हैं? क्या आपने संक्टेश्वर जी के यहां भेज दिया किसके यहां आपने भेज दिया, लेकिन वे कहते हैं कि हमने भेज दिया तो ऐसी बात है अध्यक्ष महोदय, हर विभाग की ये समीक्षा तो करें, मैंने शुरू में ही कहा कि किस-किस विभाग की मैं बात करूं, सभी विभाग में इसी तरह की बात है। मैं खास करके ग्रामीण-विभाग के माननीय मंत्री से कहूंगा कि वे अपने विभाग की समीक्षा करें, ग्रामीण विकास विभाग के कार्यो की समीक्षा होनी चाहिये।

अध्यक्ष : आज बोलने वाले सदस्यों की लम्बी सूची है इसलिए आप समाप्त कीजिए।

श्री संकटेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही बहुत सारी बातें कहीं हैं और मांग रखी है जिसपर सरकार को विचार करना होगा और सरकार को संवेदनशील होना होगा। जिसतरह ने इन्होंने समाज को लड़ाने का काम किया है, समाज को दूषित करने का काम किया है उससे समाज को बचाना होगा और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाना होगा, विधि व्यवस्था कंट्रोल करना होगा और शिक्षा नीति में सुधार करना होगा और उसको कार्यान्वित करना होगा। छोटानागपुर में जितने माईन्स हैं उनको देखना होगा तब ही आगे काम हो सकता है अन्यथा उपोशंखी घोषणाओं से, सरकार चलाने से आम जनता को आपके प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है, मैं आपको पहले से आगाह कर देना चाहता हूँ।

श्री फुरकान अंसरी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि आप गांधीवादी हैं और महाराष्ट्र में जो गांधी के हत्यारों द्वारा कार्रवाई हो रही है जिसके बारे में आपने कहा था कि वाद-विवाद करायेंगे और आज वाद-विवाद नहीं करा रहे हैं लोग कैसे समझेंगे कि आप गाँधीवादी हैं। आप महात्मा गांधी के हत्यारों के विरूद्ध

वाद-विवाद करावईयें।

श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, गांधी जी के हत्यारों पर राष्ट्रद्रोह की कार्रवाई...........

अध्यक्ष : आप शोर मत कीजिए। शोर करने से कुछ नहीं होता है।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, हिन्दी केशरी यादव, माननीय सदस्य जी कह रहे हैं उसके संबंध में बोलने की इजाजत दी जाय कि हम कुछ बातें कहें।

श्री हिन्दी केशरी यादव : उनलोगों पर राष्ट्रद्रोह का मामला चलाईयें।

अध्यक्ष : अगर इस बिहार राज्य का 9 करोड़ आदमी देश भक्त हो जाय तो बिहार का कल्याण हो जायेगा। आप बैठ जाईये।

श्री हिन्द केशरी यादव : गांधी के हत्यारों ने राष्ट्राद्रोह का कार्य किया है, उनलोगों पर कार्रवाई की जाय।

अध्यक्ष : सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आयेगा तब कुछ होगा। अभी बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : हाऊस नहीं चलने दीजियेगा? बैठिये न। माननीय सदस्य श्री योगेन्द्र प्रसाद शाहु को बोलने दीजिये। आपलोग कितनी शांत थे, कितना बढ़िया से हाउस चल रहा था। हाऊस को चलने दीजिये। शांत रहिये।

श्री हिन्द केशरी यादव : अध्यक्ष महोदय, इस पर कब निर्णय होगा?

अध्यक्ष : पहले बजट पास होगा उसके बाद दूसरा काम होगा। श्री योगेन्द्र प्रसाद साहू आस भाषण प्रारम्भ करें।

श्री योगेन्द्र प्रसाद साहु : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की ओर

से अनुपूरक व्यय मांग सदन की मंजूरी के लिए प्रस्तुत हुई है और उसके खिलाफ माननीय सदस्य चन्द्रमुखी जी का कटौती प्रस्ताव भी सदन के सामने आया है। मैं सरकार की मांग के समर्थन में और चंद्रमुखी जी के प्रस्तावित कटौती प्रस्ताव के विराध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने वित्तीय वर्ष 1998-99 में विभिन्न विकास कार्य योजनाओं को बिहार की धरती पर उतारने के लिए कमजोर वर्ग की आर्थिक सेहत को बनाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाकर एक समतामूलक समाज, नये समाज की संरचना के लिए जो बजट प्रस्तुत किया है उससे हमारी सरकार को संतुष्टि नहीं हुई, हमारी सरकार चाहती है उससे भी ज्यादा विकास का कार्य हम इस वित्तीय वर्ष में अपने हाथ में लेकर अच्छे समाज के निर्माण की दिशा में अग्रसर हों इसलिए हमारी सरकार को यह अनुपूरक बजट पेश करना पड़ा।

श्री राम लाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि अभी दो दिन पहले हमलोगों ने बजट पास किया है, पुनः सप्लीमेंट्री पेश किया जा रहा है उसका क्या औचित्य है, एक ही बार बजट पास क्यों नहीं करवा लिया गया?

श्री योगेंन्द्र प्रसाद साहु : आप धीरज के साथ सुनिये तो सही। अध्यक्ष महोदय, मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सदन के सामने व्यान किया कि इस वित्तीय वर्ष में विकास कार्यो में जो धन राशि खर्च करना चाहिए था उसके संबंध में मुख्य बजट पेश किया गया लेकिन सरकार के सामने बिहार की गरीब गुरबा की अर्थिक जिन्दगी में सुधार और उसके लिए विकास कामों में और बाहूलता लाने की आवश्यकता महसूस की गयी और उस बजट से काम चलने वाला नहीं था इसलिए इस सत्र के अंदर अनुपूरक बजट पेश कर बिहार की आर्थिक सेहत को ऊंचा उठाने की दिशा में कदम बढ़ा गया है। अध्यक्ष महोदय, सदन अच्छी तरह जानता है, सूबे बिहार के ही लोग नहीं

बल्कि पूरा हिन्दुस्तान जानता है कि बिहार की लोकप्रिय राबड़ी देवी की सरकार है वह हमेशा से गरीब गुरबा, दवे कुचले लोग, गरीब इन्सान; दलित अकलियत के लोग जो समाज में पिछड़े दर्जे के लोग माने जाते थे, पिछली कतार के लोग थे जिनकी आर्थिक समाजिक राजनीतिक जीवन में पिछड़ापन आया हुआ था वे हर क्षेत्र में अलग और हाशिये पर रखे गए थे उनके चतुर्दिक विकास के लिए लगातार प्रयत्नशील रही और लगातार प्रयत्न के बाद आज हमारी सरकार इस स्थिति में है कि कमजोर वर्ग के लोगों के, गरीबों के, दलितों के, अकलियतों के और तमामा ऐसे दवे कुचले लोगों के आर्थिक समाजिक और राजनीतिक जीवन में एक अच्छा उछाल लाकर एक अच्छे समाज की रचना की तरफ हमारी सरकार बढ़ रही है इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं इस सप्लीमेंट्री मांग का फुजोर समर्थन करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि इस मांग को पारित होने दें और साथ ही साथ हमारे प्रस्ताव के खिलाफ जो अभी कटौती प्रस्ताव पेश करते हुए माननीय सदस्य श्रीमती चन्द्रमुखी देवी जी ने बाढ़ की भीषण स्थिति का बयान करते हुए कंकड़बाग की दशा और दिशा पर चिन्ता व्यक्त की थी।

अध्यक्ष : अब आप बैठिये। माननीय सदस्य श्री यमुना यादव जी प्रारंभ करें।

श्री यमुना यादव : अध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से एक अच्छा सुझाव आया है, उसका मैं सपोर्ट करता हूं और आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि सरकार आज ही उसके बारे में कुछ आश्वासन दें। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से मा0सदस्य श्री अजीत सरकार की हत्या के बाद सरकार ने घोषणा किया है कि हम उनकी विधवा को 10 लाख रूपया देंगे, बच्चों की पढ़ाई सरकारी खर्चे पर होगी, पटना में उनको मकान दिया जायेगा, तो मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो सुविधा स्व0 अजीत सरकार की विधवा को दिया गया है, वही सुविधा स्व0 बृज बिहारी प्रसाद की विधवा को भी दी जाय। मैं चाहूंगा कि इसपर आज ही सरकार का आश्वासन हो।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने फैसला लिया है, अजीत सरकार की विधवा को जो-जो सुविधा दी जायेगी, वही सुविधा स्व0 बिहारी प्रसाद की पत्नी को भी दी जायेगी।

श्री रामदेव वर्मा : यह सुविधा कब तक दीजियेगा?

(व्यवधान)

श्री तारकेश्वर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व सदस्य स0 अशोक सिंह जी भी 1995 से 2000 के बीच के विधायक थे, उनकी भी हत्या कर दी गयी। उनकी विधवा को आज तक कोई सुविधा नहीं दी गयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि जो सुविधाएँ स्व0 अजीत सरकार एवं बृज बिहारी प्रसाद की विधवा को दिया जा रहा है, वही सुविधा स्व0 अशोक सिंह की पत्नी को भी दिया जाय।

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य श्री तारकेश्वर प्रसाद सिंह जी ने जिस सवाल को उठाया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मा0 सदस्य श्री अशोक सिंह जी के परिवार को भी तमाम सुविधा दी जानी चाहिए जो सुविधा अजीत सरकार की पत्नी एवं बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी को दिया जा रहा है, वही सुविधा अशोक सिंह जी की पत्नी को भी दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री तारकेश्वर प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार को इसपर जवाब देना चहिए।

अर्जुन राम : अध्यक्ष महोदय, मैं इस कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को बतलाना चाहता हूँ

कि आजादी के बाद इस बिहार की धरती पर जितनी ही दवा हुई उतना ही मर्ज बढ़ता गया है। उदाहरणस्वरूप मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि हर साल बजट की राशि बढ़ायी जाती है और विकास कार्य कुछ नहीं होता है। पहले मैं शिक्षा विभाग को ले रहा हूँ।

महोदय, शिक्षा विभाग में आज इतनी अराजगता है जिसे तमाम माननीय सदस्य जान रहे हैं आज बिहार में 20 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनका कोई भवन नहीं है। उस विद्यालय में छात्र पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। उस विद्यालय के छात्र गर्मी और बरसात में अपने-अपने घर चले जाते हैं और यह सरकार कहती है कि हम बिहार में शिक्षा को उन्नतशील बनायेंगे, हम बिहार को साक्षर बनायेंगे। साक्षर बनाने के लिए अरबों-अरबों रूपया खर्च किया जा रहा है लेकिन सच्चाई यह है कि आजादी के बाद से आजतक साक्षरता के लिए जो पैसा खर्च हुआ, वह व्यर्थ खर्च हुआ क्योंकि निरक्षरों की संख्या घटनी चाहिए थी लेकिन दिन-पर-दिन उनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैंने कहा कि जितनी ही दवाइयां हो रही हैं, उतना ही मर्ज बिहार में बढ़ता जा रहा है। अभी शिक्षा पर अरबों-अरबों रूपया खर्च हो रहा है प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, जन शिक्षा एडेल्ट शिक्षा और अनोपचारिक शिक्षा के माध्यम से लेकिन शिक्षा में कोई परिवर्त्तन नहीं आया है। बिहार के निरक्षरता एक अभिशाप के रूप में बना हुआ है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि शिक्षा पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने इतना रकम बजट के रूप में पास किया और हर साल बजट बढ़ती जा रही है लेकिन हमारा शिक्षा उन्नत क्यों नहीं होता है, निरक्षर की संख्या क्यों नहीं घटती है। यह तो शिक्षा विभाग की बात है।

अब मैं सड़के के बारे में बतलाना चाहता हूँ। आज बिहार के सभी ग्रामीण सड़कों की हालत बहुत जर्जर है। हम विधान-सभा के माध्यम से बजट बढ़ाते हैं लेकिन आज ग्रामीण सड़कों की हालत बहुत ही जर्जर है

और बरसात के मौसम में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, गांव मं जाने में कितनी समस्या होती है, इसे हर माननीय सदस्य जान रहे हैं। इसी तरह पथ निर्माण विभाग की सड़कों की हालत है। यह मैं ही नहीं बल्कि माननीय हाई कोर्ट ने भी कहा है कि बिहार में पथ निर्माण की सड़कें बर्बाद हो गई हैं। यह आप और तमाम सदन के लोग जानते हैं कि बिहार के पथ निर्माण की सड़कें चलने लायक नहीं रह गई है। मैं माननीय मंत्री के क्षेत्र और जिला की बात कह रहा हूँ। मैं यह दावा के साथ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि बक्सर-सासाराम रोड बंद हो चुका है और सासाराम माननीय पथ निर्माण मंत्री जी का क्षेत्र पड़ता है। आप इसकी जांच करता लें। आप सदन के किसी भी माननीय सदस्य को भेजकर दिखवा लें। हमारे क्षेत्र में बखरी से सासाराम तक जाने के लिए मेन रोड है। यह बहुत बड़ा रोड है लेकिन वह रोड जाने लायक नहीं रह गया है। सब प्रकार का आवागमन ठप हो चुका है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। चकोर चारो तरफ घुमता है। उसको दुनिया बहुत बड़ी मालूम पड़ता ही लेकिन जब वह अपने पेरों तरफ देखता है तो वह उसे ब्रहुत छोटी मालूम पड़ता है। मैंने आपको क्या कहा? जब हमलोग रहते हैं तो कहते हैं।

श्री अर्जुन राम : महोदय, संबंधित मंत्री महोदय को सदन में रहना चाहिए था और हमारी बात सुननी चाहिए थी। वे नहीं हैं लेकिन अन्य माननीय मंत्री लोग सदन में हैं।

अब मैं जल संसाधान विभाग को ले रहा हूँ। महोदय, मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार को बतलाना चाहता हूँ कि बिहार में अंग्रेज के जमाने में सोन नहर बनाया गया था। आज उस नहर की हालत क्या है। सोन नहर बिहार के आठ जिलों में है। आज वह नहर नहीं रह गया है। आज यह नहर तालाब के बराबर हो गया है। इसकी विशेष मरम्मती के लिए हर साल बजट में प्रावधान किया जाता है लेकिन बजट का पैसा व्यर्थ खर्च होता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे दो मिनट का समय दिया जाए। मैं एक बात और यह कहना चाहता हूं कि जहां तक भूमि-सुधार का सवाल है, पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी सदन में घोषणा किया था कि हमारे राज्य का अगर कोई गरीब आदमी जो बिहार सरकार की जमीन चढ़ेगा, हमारी पुलिस उनपर लाठी-गोली नहीं चलायेगी। हमारा पुलिस प्रशासन और प्रशासन उनकी सहयोग करेगा। लेकिन ऐसी नहीं हुआ। आज क्या हो रहा है। आज बिहार के अंदर जब कोई गरीब व्यक्ति जिसको एक धूर जमीन नहीं है, बिहार सरकार की किसी जमीन पर चढ़ने जाता है, दखल करने जाता है तो बिहार की पुलिस और बिहार का प्रशासन उन पर जुल्म करता है। यह एक सच्चाई है। आज भी बिहार के अदंर जिस तरह से अनेकों मवेशी एक ही घर के अदंर रहते हैं, भेड़, बकड़ी, गाय, बछड़ा, एक ही घर में रहने के लिए मजबूर हैं उसी तरह से आज भी बिहार के 20 प्रतिशत लोग ऐसे हैं, ऐसे परिवार हैं जो एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर हैं, बेटा-पतोह, बेटी-भाई, वहन सभी एक ही छत के नीचे रहने को मजबूर हैं। इस तरह की स्थिति आज इस राज्य के अंदर है।

महोदय, अब मैं विधि-व्यवस्था के संबंध में कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूं। महोदय, राज्य के अदंर विवि-व्यवस्था की जो हालत है वह सदन के तमाम सदस्यों के छिपा हुआ नहीं है। आज सुरक्षाकर्मी खुद अपनी सुरक्षा करने में विफल हो रहे है। तो वे आम जनता की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? आज सभी जानते है कि खुलेआम दिन-दहाड़े चोरियों हो रही है, डैकतियां हो रही हैं, अत्याचार और बलात्कार हो रहे हैं, अपहरण की घटनायें बढ़ रही हैं। जहां तक मेरे क्षेत्र का सवाल है, वहां तो अपहरण की घटनाएं काफी बढ़ चुकी है। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : आदरनीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात एक मशहूर कवि की पंक्तियों से शुरू करना चाहता हूं-

"कहनी है मुझको अजव कहानी,

न ऐसी नई है न ऐसी पुरानी,

न समझी तो गैरों का है ये फसाना

जो दिल से सुने तो अपनी कहानी।"

अध्यक्ष महोदय, मैं जो दास्तांन कहने जा रहा हूं वह हरेक के दिल की दास्तांन हैं। मैं ऐसा देख रहा था कि जिस प्रकार महाभारत की युद्ध की लाईनें खींचीं हुई है, अगर इधर के माननीय सदस्य बोलते हैं तो सरकार की आलोचना और उधार के लोग बोलेंगे तो वृहत्त प्रकार की रटी-रटाई बात जैसे जितनी भी प्रशस्ती के गीत हो सबसे हैं, वह सरकार के गायेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि क्या इस महाभारत युद्ध में कि विदुर की बात भी सुनी जायेगी जो सही बात कह कर यह बताने की कोशिश करें कि आज बिहार को किस चीज की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय, इस पक्ष के साथ मैं बहुत दिनों तक रहा हूं। मैं मंत्रिमंडल का भी सदस्य रहा हूं, लालू यादव जी के मंत्रिमंडल में मैं ढाई साल तक मंत्री भी रहा हूं। जो मेरे साथी यहां पर मौजूद हैं, वह जानते होंगें कि विधायक दल की बैठकों में मैं अक्सर कुछ सुझाव देता रहा हूं अपने साथी अपने भाई लालू यादव जी को। पता नहीं दूसरे किसी को हिम्मत होती थी या नहीं। इसीलिए मैं कहं रहा हूं कि वे लोग मेरी गवाही देंगें। मैंने कहा कि प्रकृति ने लालू जी आपको अवसर दिया है। यह अवसर बहुत कम लोगों को नसीब होता है। सबको नसीब नही होता है। यह अक्षुण ताकत जो आजादी के बाद बिहार के किसी मुख्यमंत्री को प्राप्त नहीं हुई। श्री बाबू रहे होंगें। दूसरे भी रहे होंगे। अध्यक्ष : नामधारी जी। गीता के नौवें अध्याय की बात सब करें तब न और भी सार्थक हो।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि श्री बाबू रहे

हैं। वे ताकतवर माने जाते रहे थे। लेकिन उनके ऊपर स्व0 श्री जवाहर लाल जी हाई-कमान कहलाते थे। लेकिन लालू यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो वह स्वयं हाई-कमान हो गये। उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था और 8 साल का समय कोई छोटा समय नहीं होता है। अगर वे मेरी कुछ सुझावों को मान लिये होते तो आज नया बिहार वन गया होता।

श्री अवधबिहारी सिंह : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कह दिया कि श्री बाबू के ऊपर भी पंडित जवाहर लाल नेहरू थे, हाई कमान थे। हमारे यहां "ग्रूप ऑफ कलेक्टिव लीडरशीप" होता है, व्यक्ति नहीं होता है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, मैं कहा "इशारों को अगर समझो, राज को राज रहने दो"। मैं यह कह रहा था कि लालू यादव जी को मौका मिला और यह कोई छः महीने या एक साल का नहीं मिला, आठ साल का मौका था। मैंने आग्रह किया था कि लालू जी, कम से कम साल तो विकास वर्ष के रूप में मना दीजिए, विधायक दल की बैठक में शामिल मेरे तमाम साथी इस समय यहां मौजूद हैं। एक साल को विकास वर्ष घोषितकर दीजिए, इस दौरान राजनीति कम होगी और विकास का काम अधिक होगा। मेरे सुझाव पर लालू जी ने कहा था हम यही करने जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं मंत्रियों को जिलों में बैठा दूंगा। महीने में 25 दिन वे वहीं रहेंगे। अगर यह काम किया गया होता तो आज सब जगह योजनाएं स्वीकृत हो गयी होती, सड़क और पुल अधूरे नहीं रहते। मैं यह कह रहा हूं कि समय बीतता जा रहा है। इतिहास सबको याद रखता है, मेरे सुझावों पर काम नहीं किया गया। मैं आज की बात कहना चाहता हूं कि सरकार के मंत्रियों को आज क्षेत्र में भेजा जा रहा है। मंत्री जी, राबड़ी जी ने कृपा की होगी, तेरह तारीख से पंद्रह तारीख तक जहां कहीं प्रोग्राम हो रहा है, वहां के प्रभारी मंत्री पहुंचे हुए हैं। आज यह काम लगातार हो रहा है। पहले जिन मंत्रियों के दर्शन नहीं होते थे, आज वे अवरित हो रहे हैं। सारे मंत्री पहुंच रहे हैं। इन मंत्रियों को अगर

मुख्य मंत्री जी निर्देशित करें तो जिलों में होने वाली जिला-20-सूत्री की बैठकों में भी जांच, आज आफिसर निरंकुश हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, रामजीवन बाबू बजट पर बोल रहे थे। मैं यह महसूस कर रहा था कि काश कभी सच्चाई के साथ रहे होते। इलियास हुसैन जी हमारे मित्र रहे हैं। 1980 से ही मेरी कमिटि में मेरे साथ रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री इंदर सिंह नामधारी : मैंने रामजीवन प्रसाद जी के बारे में कहा है। मैं पथ निर्माण मंत्री के बारे में कह रहा हूं कि वे मेरे बहुत नजदीकी मित्र रहे हैं।

श्री मुंशीलाल राय : अध्यक्ष महोदय, इनका इशारा ठीक था। रामजीवन बाबू के समय में राज्य में 7 लाख मि0ट0 अनाज के उत्पादन में गिरावट हुई बिहार में।

श्री इदंर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, मैं यही बात मुंशी बाबू से भी कहूंगा। मैंने अपनी बात अभी शुरू ही की थी। इन्हीं से मुझे एक बात कहनी है कि इन सबको अपने सीने को टटोलना चाहिए। मैं यहां पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा कि इलियास हुसैन जी मेरे दोस्त, मित्र हैं लेकिन आज कोई भी निष्पक्ष आदमी, हिन्दुस्तान का कोई नागरिक अगर बिहार की सड़कों पर घूमे और सड़कों की हालत के लिए बधाई दे तो मैं नत-मस्तक हो जाउगा लेकिन आज स्थिति यह है रोड जाम हैं चार-चार दिनों तक, छः-छः दिनों तक, गाड़ियां पास नहीं हो रही हैं। बिहार की धरती पर आते ही समझ जाते हैं कि किस राज्य में चल रहे हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्री को यह निर्देशित नहीं करना चाहिए कि आप सड़कों का निरीक्षण कीजिए, सड़कों में जहां कमी है, उसको दूर करवाना चाहिए। यह काम मुख्यमंत्री जी को अपने मंत्रियों को निर्देशित कर करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, राज्य में चल रहे विकास कार्यों की भी समीक्षा होनी चाहिए। आज जिलों में, प्रखण्डों में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के पहले 20 प्रतिशत् से 40 प्रतिशतृ तक "पी0सी0" लिया जा रहा है। अगर कोई माननीय विधायक यह कह दें कि मेरे ब्लौक में यह नहीं लिया जाता है तो मैं उनके सामने नत-मस्तक हो जाउंगा और कहूंगा कि आपने सतयुग ला दिया है बिहार की धरती पर, आप बिहार की धरती से बाहर हैं। आज मैं दावे के साथ कहता हूं कि किसी भी वी0डी0ओ0 की कमाई दो-तीन लाख है। कौन अंकुश लगायेगा? आप कहेंगे कि हमने राम-राज्य ला दिया। मैं फिर वहीं बात शुरू करना चाहता हूं। राबड़ी जी, आप मेरी बहन के समान हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं आप इन बातों को महत्व औपचारिकता से नहीं लें। जिस वक्त किसी जगह सी0बी0आई0 बैठ गया, उसकी जांच हो रही है।

उनको इस डिपार्टमेंट से हटाया जाना चाहिए था। आप उनको और बढ़िया मंत्रालाय दे देते जिससे कि उनका रूतवा और बढ़ जाय। महोदय, यह एक महत्र औपचरिकता थी लेकिन आज आठ साल से वही व्यक्ति उसी डिपार्टमेंट में बैठा है और किसी को हिम्मत नहीं है कि उसको टच करे। हम रो रहे हैं, जनता रो रही है लेकिन किसी को कहने का दम नहीं है। जनता ने आपको अधिकार दिया है लेकिन मैंने कहा है कि यह कुर्सी किसी की स्थायी नहीं हैं। आप बीस साल, पच्चीस साल तक राज कर लेंगे लेकिन एक दिन तो इस कुर्सी से हटना पड़ेगा और हटने के बाद जो पश्चाताप् होगा, शायद कुर्सी पर बैठने में उतना मजा नहीं आया होगा जितना आपको हटने के बाद पश्चाताप् होगा कि हमने समय का सदुपयोग नहीं किया।

महोदय, अब मैं अपने जिले की बात करना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी, आपके पीछे बैठे हैं, माननीय मंत्री, श्री गिरिनाथ सिंह जी, महोदय, डाल्टेनगंज और गढ़वा दो जिला मुख्यालय हो गये। दोनों की दूरी अभी हम जाते हैं परवा मोड़ होकर तो 50 कि0मी0 पड़ता है लेकिन उधर से, शाहपुर होकर मात्र 28

कि0मी0 गढ़वा से डाल्टेनमंज की दुरी है। सड़क पूरी बनी है, केवल पहले एक नदी पर पुल बनना है, जिसके पाये खड़े हैं। आज आठ साल से हमलोग चिल्ला रहे हैं लेकिन वह काम नहीं हो रहा है। यह नेशनल लौस नहीं तो क्या है? मुख्यमंत्री का 8-8 बार सदन में ध्यानाकर्षण पर उत्तर आया कि हम इसको शीघ्र बना रहे हैं लेकिन आज आठ साल बीत गया। अध्यक्ष महोदय, आत्मा रोती है, कहां 50 कि0मी0 और कहां 28 कि0मी0 की दूरी? सड़क तैयार है लेकिन पुल नहीं बन रहा है, पाये खड़े हैं। आठ बार ध्यानाकर्षण पर मंत्री जी का जवाब हुआ कि हम इसको शीघ्र बना रहे है तो आखिर हम किसको पास जाकर रोयें?

महोदय, यह सदन एक मन्दिर है, जहाँ पर यदि कोई मंत्री आश्वासन देते हैं तो आश्वासन पर भरोसा किया जाना चाहिए, हम अगर कोई बात कह रहे हैं तो हम उस काम को करके दिखायेंगे। लेकिन आज हम किसके पास जाकर रोयें? महोदय, इसी पर मुझे भारतेन्दु हिरश्चन्द्र की वे पंक्तियाँ याद आती हैं- "आओ सब मिल रोयें भाई, अब बिहार की दुर्दशा न देखी जाय"। आज सबको बैठकर रोने की जरूरत है, आज किसी एक व्यक्ति को लांछित करने की आवश्यकता नहीं है, आज रोने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, इतनी ही बात नहीं है, मैं कहना चाहता हूँ कि जब गुलाम सरवर साहब अध्यक्ष थे, अभी सदन में नहीं बैठे हैं, महोदय, नेउरा से लेकर रामकन्डा तक एक सड़क है जो माननीय मंत्री, श्री गिरिनाथ सिहं जी के कंस्टीच्यूयेंसी और हमारी कंस्टीच्यूयेंसी को मिलाता है, उसक शिलान्यास गुलाम सरवर साहब ने किया था 1991 में, 84 लाख की वह सड़क की योजना है लेकिन आज तक उसमें एक भी पत्थर नहीं गिरा है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आखिर सरकार की सैंक्टिटी क्या है? मंत्री या मुख्यमंत्री की बात की कीमत क्या है? क्या मंत्री लोग जब आदेश देते हैं तो होश नहीं रहता है कि हम इसका इम्पलीमेंटेशन कैसे करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आज यह कहना चाहता हूँ कि कुछ दिलों की बात है, जो पक्ष-विपक्ष से ऊपर उठकर सोचना होगा नहीं तो युद्ध को कोई रोक नहीं सकता है। "युद्ध की नींद कहते हो, मगर जब तलक उठ रही चिनगारियाँ, विभिन्न संघर्ष की, युद्धता तो विश्व में अनिवार्य है"। जो अनिवार्य है, उसके लिये खिन्न या परतप्त होना व्यर्थ है। "तू कहीं लड़ता, युद्ध तो होगा। मैं माननीय जयप्रकाश जी को भी कहना चाहता हूँ, वे हमारे पड़ोसी हैं, युद्ध का वातावरण मत बनाइये, इसको टालिये। अगर सही सुझाव विपक्ष से भी आता है तो उनपर ध्यान दीजिए, चुनौती देना और लेना, यह कोई बहादुरी की बात नहीं है। महोदय, न्यूटन ने कहा था, अमेरिका का जो प्रथम राष्ट्रपति था, उसका कहना था कि जो हमारे विराधी हैं या जो अखबारें हैं, वे हमारी आँखें हैं। जब अखबार लिखता है तो हम पढ़ते हैं कि क्या हमारे विभाग में भी भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर आलोचना विपक्ष के लोग करते हैं तो फिर हमें सोचना चाहिए कि क्या मेरे विभाग में भी वास्तव में भ्रष्टाचार हो रहे हैं? लेकिन आज लन्सपावर से, अपनी जुवान से हल्ला करके कहते हैं कि हम ऐसा होने नहीं देंगे? यह कोई निदान नहीं हैं महोदय, मैं जयप्रकाश जी को कहना चाहता हूँ, अगर इनकी याद होगा लालू प्रसाद जी के सामने मैंने कहा था कि आप नौजवान आदमी हैं, अगर आप चाहें तो आप शिक्षा विभाग का कायाकल्प कर सकते हैं लेकिन हाई स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए आपने जो पद्धति बनायी, आज इस पवित्र सदन में मैं आक्षेप करना चाहता हूँ कि इसमें करोड़ों रूपये का बारा-न्यारा हुआ है। एक हाई स्कूल के शिक्षक को दूसरे हाई स्कूल में ट्रांसफर करने के लिये, चाहत की सीट देने के लिये एक-एक आदमी से एक-एक लाख रूपया लिया जा रहा है। मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ वह आरोप लगा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसमें अनक्वायरी होनी चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा, अगर जयप्रकाश जी को याद होगा,

एयरपोर्ट पर राँची में 25 जनवरी को ये लोग झण्डा फहराने जा रहे थे, एयरपोर्ट पर मैंने लालू जी को कहा था कि सरकार की बहूत बदनामी हो रही है, उस समय मैं भी मंत्री लालू जी को कहा था कि सरकार की बहुत बदनामी हो रही है, शिक्षक भी समाज के साथ इनक्लूड होते हैं, इनके स्टुडेंन्ट्स होते हैं, एक-एक मूँह से यही बात हो रही है। अगर डाल्टेनगंज के किसी हाईस्कूल से राँची के किसी होईस्कूल में जाना है तो उसका रेट बंधा हुआ है। तो क्या यह स्थानांतरण किसी डॉक्टर के कहने पर हो रहा है कि स्थानांतरण होना चाहिए? अगर आपको उनका स्थानांतरण करना ही था तो आप ईमानदारी के साथ उसका इम्पलीमेटेंशन कराते। जिन-जिन आर0डी0डी0 की शिकायत आती, उनपर आप एफ0आई0आर0 करके उनको जेल में बन्द करने का काम करते और उनको कहते कि क्या हमने तुमको पैसा कमाने के लिये कहा था? अगर कोई नहीं रह गया था, 10 साल से, 20 साल से तो आप उनको वहाँ से हटा देते, उनकी लौटरी सिस्टम से बदल देते। लेकिन मैं इसका जवाब, अभी आप तैश में मत आइए। मैं चाहूँगा कि आप समय पर इसका ज़वाब दीजिए। मैं आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मैं जानता की आवाज को आपके कानों तक पहूँचा रहा हूँ। यह बात जनता की है। अगर निर्गुण है तो मुझे खुशी होगी लेकिन कुछ लोगों ने, मेरे सम्पर्क में हैं ने कहा है। स्थांतरण की पद्धति को थोड़ा और परिस्कृत कीजिए ताकि पैसे का जो लेन-देन है, वह कम हो। हरेक मंत्री अपना विभाग देखे और मुख्यमंत्री जी इसकी समीक्षा करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, थोड़ा और समय दिया जाय ताकि मैं अपने साथियों के दिल की बात कह सकूँ क्योंकि अभी महावीर बाबू हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ। माननीय सदस्य नामधारीजी की सारी बातें सदन सुन रहा था। बहुत पुराने

मेम्बर हैं और उनकी बातों का मैं कद ... रता हूं। जो भी ट्रॉसफर-पास्टिंग की पुरानी व्यवस्था ... था, उसको चालू नहीं किया गया था। जो 437 थे, उसके तहत बार-बार ट्रॉसफर-पोस्टिंग होनी चाहिए, उसी को हमलोगों ने ने चालू किया। ऐसी बातें आयी गयी। मैं कहना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट का आदेश था कि 437 के तहत शिक्षकों को स्थांतरण-पदस्थापन होना चाहिए। हम इसे नही कर रहे थे लेकिन उसको किया भी गया ओर उसके नतीजे बेहतर भी आये। कुछ नतीजे खराब भी होंगे लेकिन सरकार की मंशा है। हम किसी शिक्षक को बुरे जगह में दे दें, खराब कर दें, पैसों का लेन-देन करें, ये नहीं कहें यहाँ क्योंकि यह सब कुछ नहीं हुआ है। सरकार इस मामले में कही है कि डिसट्रक्टिव बातों को सुधारना है, बेहतर बनाना है। मेरा जो भी धर्म है, उस धर्म से आगे बढ़े हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्दरसिंह नामधारी : बैठिए रामाधार जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ और बड़ी-ही संयत से बोल रहा हूँ। मैं किसी को हाथ हिलाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी साथी की भावना को ठेस लगे। "आई वील द लास्ट मेर टूडू इट" लेकिन मैं एक बात सुझाव के तौर पर कह रहा हूँ कि आपने आज उसपर से, डाक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबंध लगाया। अखबारों में तो बहुत-सी बातें आयी लेकिन महावीर बाबू समाज में जो अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है, उसको आप देखिए। डाक्टरों की प्रैक्टिस जारी है। बंद है या खुला, आप ही बतायें हम लोगों को तो पता नहीं चल रहा है। आप ज्यादा समझदार हैं क्योंकि आपके नाम के आगे भी डाक्टर लगा हुआ है। आप भी डाक्टर हैं, इसलिए शायद आप ही जानते होंगे। बिहार की जनता पूछ रही है कि यह पाबंदी लागू है या नहीं लागू है। डाक्टर पूर्जा काट रहे हैं और उसपर से अपना नाम काट लिये हैं। जब सरकार को पाबंदी लगानी थी तो फर्म कमिक्सन जो उन्हें करना है।

"यकीं मंहकम अमल पैहम,

मुहब्यत फातेहे आलम,

जेहादे जिन्दगानी में है,

यह मर्दो की शमशीरें।"

ये मर्दो की शमशीरें होता है कि यकीं महकम अटल विश्वास के साथ आगे बढना। मैंने सोच लिया तो सोच लिया, तभी यह होता है। डाक्टर कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे। यह क्या सरकार है? कोई कर्मचारी कहे कि हम सरकार के आदेश को नहीं मानेंगे। किसकी हिम्मत है कि नहीं मानेगा लेकिन आप अपने ढुलमुल हैं। आपके दिल में कोई निश्चिय नहीं है, आप डगमगा रहे हैं। तो क्यां यही कानून बिहार की धरती पर लागू हो सकता है। आपने अच्छा काम किया कि प्राइवेट प्रैक्टिस को बन्द किया, प्रइवेट प्रैक्टिस बन्द होना चाहिए। महोदय, जो रेफरल अस्पताल बने हैं, उसमें लाखों रूपये का लागत है। मेरे क्षेत्र भंडरिया में एक रेफरल अस्पताल है और वहाँ पर अच्छे-अच्छे एक्यूपमेंट हैं लेकिन डाक्टर दूरबीन लेकर नहीं मिलेगा। कहीं डाक्टर नहीं हैं। डाक्टर चाहते हैं कि हम रांची में रहे, पटना में रहे और ज्यादा-से-ज्यादा नीचे जायें तो जिला मुख्यालय में रहे। देहात में तो जाना ही नहीं चाहते हैं। आपने कैसी पद्धति बनायी है, इसलिए महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि महावीर बाबू से कि वे मित्र हैं और बड़े भाई भी हैं। आपने लागू किया पाबंदी तो मर्द वाला काम कीजिए, तभी आप अच्छा काम कर सकते हैं। मैं तो राज्य-मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ। राज्य मंत्री ने कहा कि जो डाक्टर प्रैक्टिस करेगा, उसको हम जेल में बन्द करेंगे लेकिन आपने खंडन कर दिया कि उन्होंने गलत कहा है। यह जो सरकार चल रही है, यह सरकार चलाने का ढंग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी

देवी जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं औरत को कमजोर नहीं मानता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई भी औरत थी और इन्दिरागांधी भी औरत थी, कम-से-कम शासन करके तो दिखला दिया कि शासन कैसे चलाया जाता है। मंत्री जी आपसे डरे नहीं। अगर आपने एक बार कहा कि 13 मई से लेकर 15 मइ तक जिला में जाओं और तीन दिन रहा तो मैंने जिन मंत्रियों को कहा कि आपलोग एकदम परपानेंट डेरा डाल दिए यहाँ पर, कहा आदेश है। तीन दिन रहना है।

अगर भागे हैं तो मंत्री परोक्सी मारकर भागे हैं मंत्री लोग जिलों से। मत कहियेगा डी0सी0 को कि हम जा रहे हैं, क्योंकि 15मई तक रहने का आर्डर था। आप पूछिये एक-एक मंत्री से कि वे 20 सूत्री की बैठक में कितनी-कितनी बार गये हैं। मंत्री के जाने से ऑफिसर लोग डरते हैं, चूंकि उस बैठक में ऑफिसर और विधायक रहते हैं और वे कहते हैं कि अमुक स्कीम लिया गया और वहां घूस लिया लिया गया है और यह स्कीम बिना बैठक किये हुए पारित हो गया, मंत्री था, आप रेकर्ड देख सकते हैं, हर डेढ़ महीना में हम 20 सूत्री की बैठक करते थे, एक नियत समय बैठक का था, उस दिन बैठक करते थे। सारे ऑफिसर थर-थर करते थे कि किसी स्कीम पर लोग देखने न चले जायं। उस बैठक में सारे विधायक, ऑफिसर, डी0सी0, कमीश्नर साथ रहते थे और वातावरण रहता था। आप केवल यही कर दीजिए कि मंत्री लोग एक-डेढ़ महीना में 20सूत्री की बैठक करें तो आधा करप्सन इसी से दूर हो जायेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मंडल जी को बधायी देना चाहता हूं, अर्जुन मंडल जी गढ़वा के प्रभारी मंत्री हैं, ये अक्सर वहां गये हैं। आप अपनी सफाई मत दीजिए, मैं आपके पक्ष में बोलना चाहता हूं। इन्होंने एक बहुत अच्छे ढंग से जिला में प्रभारी मंत्री का काम किया है और समय पर

जाकर ऑफिसर को हिदायत दिये हैं कि ठीक से काम करें। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, आदमी को कुछ आत्म मंथन करना चाहिए। ये बातें इसलिए है और मैं कहना चाहता हूं कि यह काम मुख्य मंत्री का है। मैंने लालू जी को कहा था, हमारी यह हसरत रह गई कि कभी आप बुलाकर पूछते कि तुम विभाग में क्या कर रहे हो, तुमको क्या दिक्कतें हो रही हैं, कभी पूछा नहीं। बातें होती थी, राजनीति की बातें होती थी लेकिन यह हसरत रह गई कि कभी बुलाकर पूछते । मैं चाहता था कि जहां मेरी दिककते हैं, मैं मुख्य मंत्री के सामने बताऊं कि यहां मुझे दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि पावर तो सब मुख्यमंत्री के हाथ में रहता है। मंत्री चाहे जितना भी डिंग हांक लें लेकिन प्रजातंत्र में प्राईम मिनिस्टर के हाथ में जो पावर है, वही डेलीगेट करता है सारे मिनिस्टर को और इस प्रदेश में मुख्य मंत्री के हाथ में पावर है और वे डेलीगेट करते हैं प्रत्येक मंत्री को। आप केन्द्र में चले जायं, राज्यमंत्री हैं केन्द्र में, उनको काम करने की पचित्रता है, सांख्यिकी हैं। मंत्री बड़े-बड़े फैसले लेते हैं, मंत्री लोक सभा में जवाब देते हुए कमीटमेंट करते हैं कि काम करेंगे, यहां पर स्थिति यह नहीं हैं। आपके मंत्री ठीक से फंक्सन करें तो उनको भी लगेगा कि अधिकार उनके पास है, नहीं तो मंत्री संतरी बन जायेंगे।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि प्रवेश में बहुत सिनियर मंत्री हैं, अगर छोटा-मोटा थ्रील हो जाता है, मेम्बर पकड़ लेते हैं, इधर देखते हैं कि हम क्या कहें, पता नहीं कह दें और यह माना जायेंगा कि नहीं माना जायेगा। आप विभाग के मंत्री हैं, मंत्री नीति विषयक निर्णय लेने में सक्षम हैं और मुख्यमंत्री को भी इतनी आजादी देनी चाहिए कि वे निर्णय लें और जब मंत्री फंक्सन करेंगे तो एक अच्छा वातावरण बनेगा और जिस करप्सन की बात दिन-रात हमलोग करते हैं विधान-सभा के माध्यम से, प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण के माध्यम से, उसमें बहुत बड़ी कमी आयेगी और इस प्रदेश का वातावरण बदलेगा। इसलिए मैंने कहा, हम अपने साथियों से कहना चहता हूं अध्यक्ष महोदय,

आपके माध्यम से कि आज एक साथ उड़ान भरने की आवश्यकता है। पंचतंत्र में हमने एक कहानी पढ़ी थी। एक कबूतर पर वहेलिया ने जाल फेंका और 100 कबूतर फंस गया, उसमें बूढ़े कबूतर ने कहा कि अब तो हमलोग फंस गये, थोड़ी देर के बाद यह बहेलिया हमलोगों को कत्ल कर देगा, हम शाम तक किसी का भोजन बन जायेंगे। अगर हिम्मत है तो एक काम करो 100 कबूतर एक साथ पंख मारो और जाल समेत उड़ जाओ, पंचतंत्र की कहानी कहती है और उस बूढ़े कबूतर की बात सुनकर 100 कबूतरों ने एक साथ उड़ान भरी और जाल समेत उड़ गये ओर वह वहेलिया टुकुर-टुकुर देखता रह गया। आज वहेलिया ने हम सब पर जाल फेक दिया है। मैं अपने साथियों से कहना चाहता हूं, विधायकों से कहना चाहता हूं, मंत्रियों से कहना चाहता हूं, आज सबको एक साथ पंख मारकर उड़ने की जरूरत है, आप गुनगान मत गाईये। जहां कमी है, एक तरफ आप रोते हैं, और जब विधान सभा में बोलने के लिए उठते हैं या विधायक दल की बैठक में बैठते हैं तो आपको हिम्मत नहीं होती कि हम बधायी देते हैं फंलाने को। आप मंत्री होते हैं और आप वह देते हैं कि ठीक हैं, आप वाला ट्रांसफर हम कर देंगे। लालू यादव इसमें माहिर थे एकदम। जब कोई आलोचना करता इधर से तब तो कह देते कि ठीक है- रात में जो कहले बरा, वह हम कर देम, अब बैठ जाय।

हम यह कहना चाहते हैं कि आज प्रजातंत्र को मखौल नहीं बनने दीजिएं केवल कोई किसी पर वार करे यह अच्छी बात नहीं। आज हम सब को बैठकर चिन्तन करने की आवश्यकता है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है।

श्री जगदानन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे वीरय साथी श्री नामधारी जी सदन में बोल रहे हैं। इन्होंने सदन में काफी अच्छी बात कहीं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि माननीय नेता विरोधी दल जनता द्वारा चुनी गयी सरकार पर 356 धारा लगवाना चाहते हैं। क्या इससे लोकतंत्र सुरक्षित रह जायेगा?

क्या विधान सभा में इस तरह की बात कही जायेगी?

अध्यक्ष : मैंने कहा है कि इधर से भी और उधर से भी जो इस बात पर टोका टोका की गयी है सब को हटा दीजिए।

श्री रामाश्रय प्र० सिंह : अध्यक्ष महोदय,..........

श्री इन्दर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त कर लूं। माननीय सदस्य रामाश्रय बाबू जो हर कांग्रेस सदस्य का समर्थन करने के लिए उनका दो तीन मिनट का समय वे ले लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, जगदानंद बाबू यहां बैठे हुए हैं। मैं मानता हूँ कि आप जगदानंद बाबू अध्ययन करते होंगे। आपने अपने एडवोकेट जेनरल का स्टेटमेंट पढ़ा होगा। आपके एडवोकट जेनरल श्री राशि अनुग्रह, जो कंस्टिच्यूशनल हेड हैं जो विधान-सभा का पदेन सदस्य होते हैं। जब सरकार किसी सकते में पड़ती है तो उनको बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है कि मार्गदर्शन कीजिए। वह एडवोकेट जेनरल आपका कहता है कि सारे बिहार का तंत्र भ्रष्ट हो चुका है एक-एक अफसर भ्रष्ट हो चुका है। जगदानंद बाबू, अगर आपने पढ़ा है तो आप कहिये कि हम पढ़े हैं अगर नहीं पढ़े हैं तो हम उस दिन का अखवार दे देंगे, आप पढ़िये। यह उनका स्टेटमेंट है। आप उनसे पूछिए कि आपको आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारे बनाये हुए एडवोकेट जेनरल ही हमारे बारे में क्या कहते हैं।

श्री जगदानन्द सिंह : उन्होंने कहा है कि हमने ऐसी बात नहीं कही है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : अगर शशि अनुग्रह बाबू का कोई खंडन किसी अखबार में छपा है तो उस अखबार की प्रति आपको सदन में रखनी चाहिए। उसे सदन के सामने पेश कर दें तब हम समझेंगे कि सरकार इस पर संवेदनशील है। अध्यक्ष महोदय, हमारे पलामू जिला के 20-सूत्री के प्रभारी श्री उदित राय जी यहां बैठे हुए हैं, वे हमारे मित्र भी हैं। पिछली बैठक वहां 13 मई को हुई थी, बैठक में बड़े गुस्से में वे आये। लातेहार के पी0डब्लू0डी0

के कार्य0अभि0 कभी किसी मिटींग में नहीं भाग लेता है। मंत्री जी ने डी0सी0, पलामू को कहा कि उसको हाजिर करो। उसने छुट्टी का दरख्वास्त देकर चला गया। हालांकि उसे मंजूर नहीं किया गया। मंत्री जी उस दिन गुस्से में आये ओर बोले कि उसको सबक सिखा देंगे। मैंने कहा कि उदित जी औकात से ज्यादा मत बोलिये आप उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने मिटींग में यह बात कहीं कि आप उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। आप कया बिगाड़ लीजियेगा हमको बताईए। क्या किये अभी ढ़ाई महीने हो गये। हमारे क्षेत्र में सतवरवा में जो पथ डाल्टेनगंज को जाती है, उस पथ में बड़े-बड़े गड्ढ़े हो गये हैं। एक ट्रक का गुल्ला रोड पर ही टूट गया है। सड़क कई दिनों से जाम है। डाल्टेनगंज का एक्जक्यूटिव इंजीनियर पैसा निकालता है 20 लाख रूपया और 1 लाख रूपया अपने सहायक अभियंता को देकर शेष 19 लाख लेकर कहां जाता है पता नहीं। हम लोग उसे खोजवाते रहते हैं। यह क्या पद्धति लागू हो गयी है बिहार में, और हमारे सत्ता पक्ष के साथी कहते हैं कि हम बधाई देते हैं। क्या यही प्रगति के रास्ते पर हमारा प्रदेश चल रहा है। यह वही बात है। अध्यक्ष महोदय, जब मैं ट्रांसपोर्ट में था तो उस समय एक ट्रक सड़क पर उल्टा था। उसका चारो चक्का ऊपर में था और उस पर लिखा था हम प्रगति के पथ पर जा रहे हैं। हमने ड्राईवर को कहा यह कौन सह तरीका है। अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूँ अपने विधायकों से मंत्रियों से कि क्या इसी तरह से आंज हम प्रगति के रास्ते पर जा रहे हैं?

अभी शशि बाबू कह रहे थे कि कुत्ता काटने की दवा, साँप काटने की दवा अस्पतालों में नहीं हैं। महावीर बाबू, आदमी काट ले तो आदमी बच भी जाए लेकिन कुत्ता और सॉप काटने की दवा नहीं है। शशि बाबू आपने कहा न कि नहीं है, अब मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, केवल एक नमूना है- टाप्स ऑफ दी आई-साइट" और उदित राय जी को कहना चाहता हूं, आज भी इस सदन में हैं, आपको चैलेंज करता हूं कि हिम्मत है तो आज उस इक्जीक्यूटिव इंजीनियर का कुछ भी बिगाड़ लीजिए। आपकी मिटिंग में नहीं

सामने अपने दिल के मलमले, अपने दिल की जजवात आपके समने रखूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस पथ के साथी भी और इस पक्ष के साथी मिल कर कोई उपक्रम करें, कोई ऐसा तरीका निकलें, एक साथ काम करें, तो शायद इस बिहार का कल्याण हो क्योंकि-समय शेष है (अभी लड़ाई बाकी है)

इस कुकृत्य का,

भागी नहीं व्याध,

जो तटस्थ इतिहास गिनेगा

उनका भी अपराध।

महोदय, जो चुप-चाप बैठेंगे, जो मौन रहेंगे, इतिहास उनको क्षमा नहीं करेगा, इसलिए हमलोग मिल कर नया बिहार का निर्माण करें। छीछलेदार-एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप-प्रत्यारोप और इधर से तोते की तरह रटना बंद करें कि यह सरकार सतयुग ला दिया है। जो सही बात है वह कहिये, मुख्य मंत्री को कहिये, विधायक दल की बैठकों में कहिये। यह ठीक है कि सदन की मर्यादा में रहिये कि हमको पक्ष में बोलना है लेकिन सही बातों पर चलियेगा तो बिहार का कल्याण होगा, नहीं तो मर बार जो हुआ है- हम क्या थे, क्या हो गये और क्या होंगे।

महोदय, एक जमाना था अध्यक्ष महोदय। आप तो पुराने हैं, आप 1952 में जीत कर आये थे, तब श्री बाबू यहां के मुख्य मंत्री थे। आजादी के बाद "बिहार वाज कंडिर्ड टु वी द वेस्ट ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट"। रफीक आलम साहब पुराने आदमी हैं, यह प्रदेश हिन्दुस्तान में सबसे अच्छा प्रशासित राज्य माना जाता था, यहां का प्रशासन सबसे चुस्त था, लेकिन "इट इज द वर्स्ट ऐडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट इन द कन्ट्री"। हम पचास सालों में कहां से कहां पहुंच गए। हम क्या थे, क्या हो गये और क्या होंगे। यह पूरे देश में आज सबसे

जाएगा क्योंकि उसको किसी का डर नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं.........

(व्यवधान)

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : महोदय, छोड़ने की क्या बात है, कुछ लोग के बारे में पता करना चाहिए कि इनके परिवार का कोई ठीकेदारी तो नहीं करता है।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : इसकी जानकारी एकदम ली जानी चाहिए।

श्री महेश्वर प्रसाद यादव : गाड़ी का चक्का खुलता है, गाड़ी रूकती है, जाम होता है, दोनों में से कोई संबंध हो।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, इतना मैं कह दूं कि अगर किसी को शक हो तो इन्क्वायरी करा दें, मेरा कोई रिश्तेदार ठीकेदार नहीं है। यह मैं बहुत साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं- न आगे आने वाले समय में, और न पीछे कभी। मेरा दूर से भी कोई रिश्ता नहीं है। मैं कहना चाहता हूं अपने साथियों से, खास कर मंत्रियों से और अपने मित्र इलियास हुसैन जी से। मैं कहना चाहता हूं काश।

(व्यवधान)

मैं आलोचना की दृष्टि से नहीं, मैंने कहा कि मेरे बहुत अजीज मित्र है, दोस्त हैं, इतना समय, आठ सालों को पीरियड, आजादी के बाद कोई मंत्री आठ साल पी0डब्लू0डी0 मंत्री नहीं रहा, आप भी रहे थे अवध बाबू, लेकिन दो माह, एक माह, चार माह- आठ सालों का लम्वा समय- एक बार आप सड़कों पर घूम जाइये- कायाकल्प हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कोशिश की है कि थोड़े समय में आपके

बड़ा शोषित प्रदेश है।

(व्यवधान)

धन्यवाद श्रीमान्।

अध्यक्ष : वित्त मंत्री।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल: महोदय.....

(व्यवधान)

श्री सुशील कुमार मोदी : महोदय, एक मिनट। एक बात मैं केवल यह दूं-चूंकि आदरणीय जगदाबाबू ने यह कह दिया कि नेता विराधी दल ने कोई असंवैधानिक बात की है चुनी हुई सरकार को गिराने की बात कह कर। मैं केवल उनसे यह कहना चाहूंगा कि मैंने तो असंवैधानिक वात की है लेकिन जब पूरे राज्य के प्रशासन का संचालन लालू प्रसाद के रूप में एक असंवैधानिक सत्ता।- अणेमार्ग में बैठ कर कर रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है और वैसे असंवैधानिक सत्ता के रहते हुए ......

अध्यक्ष : माननीय विरोधी दल के नेता, मोदी जी, ...

श्री जगदानन्द सिंह : महोदय, फिर एक गलत कही गई। यह बात तो दर्ज भी नहीं होनी चाहिए और मैं सख्त एतराज करता हूं माननीय नेता, विरोधी दल के वक्तव्य पर कि कोई भी सरकार असंवैधानिक रूप से चल रही है। इस सरकार के मुखिया श्रीमती राबड़ी देवी जी हैं और उनके नेतृत्व में यह सरकार अच्छे ढंग से चल रही है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वह याद है। मैं बोलबाउंगा। आपके दल का मुझे याद है। वह याद है, मैं बोलवाउंगा।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद टेकरिवाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो अनुपूरक व्यय विवरणी प्रस्तुत किया गया है, उपस्थापित किया गया है उसमें 515 करोड़ 21 लाख 69 हजार रूपये के व्यय को ब्योरा है। महोदय, यह इस बात का प्रतीक है, इस तथ्य का प्रतीक है कि हम विकास की ओर आगे अग्रसर हो रहे हैं तेजी से। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि हमारी योजना प्रारम्भ में 1990-98 में 2462 करोड़ रूपये स्वीकृत हुयी थी जिसको बढ़ाकर हम लोगों ने 2986 करोड़ रूपया और हमलोगों ने तय किया था इसको आगे बढ़ाकर 4922 करोड़ रूपये पर ले जाते। हम आगे नहीं बढ़ सके। हमारा क़दम 3300 करोड़ रूपये पर रूक गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के वित्त मंत्री जो बिहार के हैं, यहां आये थे बहुत फैन फेयर से, पटना आये थे, हमलोगों के साथ बैठक उन्होंने की थी। उस बैठक में हमलोगों ने उन्हें बताया था कि हमारा 800 करोड़ रूपये का हमारा जो शेयर सेन्ट्रल टैक्स का, 26 प्रतिशत से 29 प्रतिशत जो किया गया, उसी के तहत आपको देना है, आप कबतक देंगे, जल्दी कीजिये। उन्होंने कहा कि अगले सत्र में संविधान संशोधन करके पैसा आपको चला जायेगा। हमारे वित्त आयुक्त दिल्ली गये थे। उन्होंने जानकारी दी कि वित्त विभाग में इसके लिये कोई सोच नहीं है, इसके लिये कोई पहल नहीं की गयी है, उम्मीद नहीं है कि कोई पैसा स्टेट को मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 143 करोड़ 57 लाख रूपया जो दशम् वित्त आयोग के तहत पंचायत को मिलनेवाला था, जो स्थानीय संस्था को मिलने वाला था, एक साल दिया गया और 1997-98, 1998-99 का रोक रखा गया। हमलोग चुनाव कराने के लिये पूरी तैयारी किये थे। सदन को मालूम है कि 80 करोड़ रूपया का हमलोगों ने बैलट बौक्स खरीदा था जब तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्री सेशन ने इन्कार कर दिया

कि हम बैलट बौक्स नहीं देंगे, हमलोगों ने बैलट पेपर छपवाया था। जो हमारा ऐक्ट था उसको लोगों ने चुनौती दी।

(क्रमशः)

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : जहाँ पंचायतों में दलितों की आबादी ज्यादा है, उसको हमलोगों ने आरक्षित किया था महोदय।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : धैर्य से सुनियेगा तो बात समझ में आयेगी, धैर्य से सुनिये। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हमलोगों ने आदरणीय वित्त मंत्री से निवेदन किया इस परिस्थिति में और उन्होंने कहा कि आप लिखकर भेज दीजिये इन सारी बातों को, हम पैसा रिलीज कर देंगे। महोदय, हमने लिखकर भेजा और लगातार स्मार देने के बाद जो उम्होंने दो पंक्तियों का जवाब दिया वह मैं सदन को बता देना चाहता हूँ। उन्होंने जवाब दिया कि हमें दुख है कि हम यह राशि मुहैया नहीं कर सकेंगे। कोई कारण नहीं बताया गया, महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि स्पेशल फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स हर साल 15 प्रतिशत बढ़ना है और उसके तहत 223 करोड़ रूपया बिहार सरकार को मिलना था। आज तक वह पैसा बिहार सरकार को उपलब्ध नहीं कराया गया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ इस सदन को कि कोयला का 95 प्रतिशत फाइन कोकिंग कोल बिहार में होता है और उसपर हम 40 प्रतिशत सेस लगाते थे जो संविधान सम्मत था, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको नल एण्ड वॉयड कर दिया तो हमारे कदम रूक गये। महोदय, जब कोयला मंत्री बिहार की माननीया कान्ति सिंह थीं तो उन्होंने एक अध्ययन दल बनाया और इस अध्ययन दल ने रिपोर्ट दिया कि ....

श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूँ। मेरी व्यवस्था यह है कि माननीय मंत्री अनुपूरक बजट पर तो कुछ बोल

ही नही रहे हैं, ये केन्द्र सरकार के वित्त मंत्री को कोसने के सिवाय और कुछ नहीं कह रहे हैं; माननीय मंत्री विद्वान मंत्री हैं, इनको अनुपूरक बजट पर बोलना चाहिए।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य फाल्गुनी बाबू, आप बैठ जायें।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : मैं कहना चाहता हूँ महोदय, 40 करोड़ हम ले जाना चाहता थे, क्यों नहीं ले गये? फ़ाल्गुनी बाबू आप पुराने सदस्य हैं, आपकी समझ में बात आनी चाहिए थी, इतनी मामूली सी बात आप नहीं समझ पा रहे हैं, इसका हमें दुख है।

महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि जो हमारा बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, भारत सरकार के डी0भी0सी0 और एन0टी0पी0सी0 को जो बकाया था 1295 करोड़ रूपया वह काट लिया हमारे एसिस्टेन्स में से, लेकिन जो हमारा बकाया है भारत सरकार के क़ारपोरेशन पर 1750 करोड़ रूपया वह हमने कहा कि हमको दिला दीजिये तो उन्होंने कहा कि दिला देंगे, सारा डिटेल्स लिखकर भेजिये। महोदय, डिटेल्स लिखकर हमलोगों ने भेज दिया लेकिन पैसा हमलोगों को नहीं मिला। यह भारत सरकार की हमलोगों के प्रति दुर्भावना है, जो दलगत नीति से प्रेरित होकर काम कर रहे हैं यह राज्य हित में नहीं है। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ महोदय, आज जो हालत है, हमलोगों की निश्चिय योजना था कि बिहार से जल-जमाव को दूर करेंगे और हम योजना बना रहे थे, लेकिन इसी बीच इन्होंने हमारे सारे पैसे को रोक लिया, वाजिब पैसों को रोक लिया और इसीलिए इसको हमको अभी स्थगित करना पड़ा। लेकिन हम सदन को बताना चाहते हैं कि हमारी यह योजना लागू होगी और बिहार को हमलोग जल जवाब से मुक्त करेंगे यह मैं माननीय सदस्यों को बता देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

आप जानकारी रखिये। महोदय, बिहार मे जो जल जमाव की समस्या

है उसमें 16 प्रतिशत पानी तो बिहार का है और 34 प्रतिशत पानी नेपाल से या दूसरे जगह से बिहार में आता है। इसके लिये हम दोषी नहीं हैं। भारत सरकार से बार बार आग्रह करने पर भी कि नेपाल में हाई डैम बनाया जाये लेकिन आज तक इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। महोदय, उससे भी हम जल जमाव की समस्या को खत्म कर सकते हैं। महोदय, आज देश की क्या हालत है।

(व्यवधान)

श्री फुरकान अंसरी : महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ इनफौरमेशन है। केन्द्र सरकार से मिलने वाली राशि को आप खर्च नहीं कर पाते हैं और हमलोगों ने अनुरोध किया है कि 20 लाख रूपया जो एक साल में देते हैं तो उसे कम से कम 40 लाख तो कर दीजिये। लोक सभा में एक करोड़ से दो करोड़ हो गया। अब हमलोग उनके सामने में इतना बौना हो गये हैं कि कोई पहचानने वाला नहीं है।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : उस पर माननीय मुख्यमंत्री बोलेंगी। आप धैर्य रखिये।

(व्यवधान)

आप धैर्य रखिये।

श्रीमती राबड़ी देवी : अध्यक्ष महोदय, चुनाव का 13 महीना रह गया। अगली चुनाव ये जीत कर आयेंगे तब 50 लाख होगा। जीत कर जो लोग आयेंगे, डेढ़ साल बाद चुनाव होगा, उसके बाद 50 लाख रूपया विधायकों को राशि दी जायेगी।

(व्यवधान)

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता

हूँ कि ये जो कह रहे हैं कि एक करोड़ की राशि को दो करोड़ कर दी गई है यह बात सही नहीं है। कल भी बयान आता है कि केन्द्र सरकार इस पर विचार कर रही है, अभी कुछ तय नहीं हुआ है।

श्रीमती राबड़ी देवी : 5 लाख जो बढ़ा है वह क्या है? पहले 10 लाख मिलता था, लालू जी ने 5 लाख हम बढ़ाये हैं, अब क्या चाहिए।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : माननीय सदस्य को जानकारी है फिर भी अनजान बन रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने सिर्फ 5 लाख नहीं बढ़ाया, 50 करोड़ जो जिला योजना को पैसा दिया वह लगभग 30 लाख छोटे आबादी वाले को। बड़े आबादी को 1 करोड़ , 1.25 करोड़ हर जिला को हर साल मिलगा। उसमें एक विधायक का हिस्सा कम से कम 15-20 लाख होगा और वह भी आप क्षेत्र की समस्या के समाधान में खर्च कर सकेंगे। यह माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। यह आपको मालूम होना चाहिए।

(व्यवधान)

महोदय, आज जो हमारी समस्या है, महंगाई का जो आलग है वह पहले 4.4 प्रतिशत था। अब वह बढ़कर 7.59 प्रतिशत हो गया है। यह महंगाई भाजपा सरकार के समय में बढ़ा है। महंगाई के बारे में महोदय मैं बताना चाहता हूं कि रूपये की किमत जो 38.6 था मार्च में, जो १७ तारीख परसो था, १७ तारीख में रूपया का मूल्य हो गया ४२.५१, यह बढ़ रहा है महोदय और महंगाई बढ रही है। महोदय, मैं बतलाना चाहता हूँ कि इसके चलते काफी हमारी जो योजनायें हैं, वे प्रभावित हो रही हैं, हम इसके लिये ज्यादा पैसा दे रहे हैं। महोदय, आज जो वित्तीय स्थिति देश की है, यह चिन्ता का विषय है

(व्यवधान)

जरा मोदी जी मुझको बोलने दीजिये ....

श्री सुशील कुमार मोदी : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। जिला योजना के बारे में जो कहा गया, सभी ज़िला में दिया जा रहा है- आप स्पष्ट निदेश दें कि प्रत्येक विधायक की अनुशंसा पर जिला योजना का १५ लाख, २० लाख रूपया खर्च किया जायेगा- यह आप स्पष्ट निर्देश दीजिये।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : महोदय, इस पर विचार कर रहे हैं, हमलोग करेंगे, हमलोग करने जा रहे है। जो योजना पर्षद का वर्त्तमान नियम है, इसमें क्या करना होगा, किस तरह से करना होगा, इसलिये हाऊस में आप ऐसा मत कीजिये जैसा कि आप कर रहे है। महोदय, मुझे दुःख है, आज भाजपा की सरकार बनी है केन्द्र में महोदय, यह देश के लिये बहुत गलत संदेश जाता है, यह फासिस्ट की सुरकार है, ये लोग हिटलर को महिमा मण्डित करते हैं, ये गोड्से को महिमा मण्डित करते हैं, इस तरह की बात होने से जब निन्दा का प्रस्ताव आने का होता है तो ये भाजपा के लोग यहां शेर-गुल करके प्रस्ताव को नहीं आने देते हैं। यह फासिस्ट भाजपा दूसरे को बोलने नहीं देना चाहते हैं और मन-मानी करना चाहते हैं, स्वेच्छाचारिता करना चाहते हैं, हीटलर, गोड्से को महिमा मण्डित करते हैं और राष्ट्रपिता की अवमानना करते हैं। फासिस्ट पार्टी जब तक देश में रहेगी ....

अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : महोदय, मैं एक बात कह कर खत्म करूंगा। महोदय, ये जो हत्यायें होती हैं, सदन में चिन्ता व्यक्त की जाती है, हमलोग भी चिन्तित होते हैं कि हत्यायें क्यों हो रही है- जहां हजारों हत्यायें हुई, जहां १० हजार करोड़ की सम्पत्ति नष्ट हुई, इसके लिये जो दोषी हुये, अगर उन्हें सहायता नहीं पहुंच रहा है और तब गृह मंत्री (केन्द्र में)बने रहें, वे अगर मानव संसाधन विकास मंत्री बने रहें तो इस देश के लिये बहुत दुर्दिन की बात है और जो ये कहते है महोदय, कि यह राजनीति बात हैं, यह राजनीति पहलू है, तो यह गलत संदेश जाता है, इसका मतलब है कि आप जो उन्होंने

किया है, ये आगे भी करन वाले हैं, चूंकि ये इसको राजनीतिक पक्ष मानते हैं- यह मुल्क के लिये बहुत चिन्ता का विषय है। माननीय सदस्य श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव को दर्द हो रहा है चूंकि इनका पर्दाफास हो रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूँ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री।

श्री तुलसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले ......

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने कहा था कि माननीय मंत्री (श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल) इन्टरवेन कर रहे हैं, इसके बाद में २-३ माननीय संदस्यों को बुलाऊंगा, लेकिन बीच में अपने मिनिष्टर को बुला दिया। अपने कहा था कि उधर माननीय सदस्यों को और इधर (कांग्रेस) के माननीय सदस्यों को बुलाऊंगा।

अध्यक्ष : आपके पार्टी के माननीय सदस्य श्री संक्टेश्वर सिंह को बुला लिया था मैंने।

श्री तुलसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने चाहे पक्ष के हों या विपक्ष के हों अपनी कीमती राय दी है, उसके लिये में उन्हें धन्यावाद देता हूं। सबसे पहले मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहूंगा कि जिन्होंने कहा है मेरी बातों पर ध्यान देना चाहिए और आत्म चिंतन करना चाहिये।

श्री ओ० पी० लाल : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश, दिल्ली की एकमात्र सड़क शेरशाह-सूरी मार्ग जी0टी0 रोड जो राष्ट्रीय उच्च पथ बना वह विगत दस दिनों से जाम है। और दिल्ली आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से आने वाले ट्रक जिस पर कच्चा सामान फल सब्ज़ी लदा हुआ है सब सड़ गया। कोयले का यातायात भी बंद है। पूरे देश में स्थिति बिगड़ गयी है।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, महेन्द्र जी ने मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ट किया है। मैंने उनको कहा है कि मैं उनको बोलने दूंगा।

श्री तुलसी सिंह : माननीय सदस्य जो सुझाव दिये हैं मैं चाहता हूं कि इनलोगों ने जो प्रश्न खड़ा किया है कि उन प्रश्नों का जवाब मैं आपके माध्यम से सदन और सदस्यों को दूं। कटौती प्रस्ताव की जो मूवर हैं चन्द्रमुखी जी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : मैं अपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर बैठे हुये हैं मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि आपने जो सवाल उठाया है महेन्द्र जी ने उठाया है और सारे लोगों ने उठाया है इन सारी बातों पर एक वक्तव्य दें।

श्री इन्दर सिंह नामधारी : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था के सवाल पर खड़ा हूं, मेरी व्यवस्था सुन ली जायं अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आपने पी0डब्लू0डी0 मंत्री से आग्रह क़िया उसमें आप इस मांग से सहमत हो सकते हैं, मैं चाहता हूं कि उसमें थोड़ा सा संशोधन करें और निर्देश शब्द का इस्तेमाल करें क्योंकि हाईकोर्ट गरिमा आसमान पर चली गयी है। हाईकोर्ट ने कहा कि डाल्टेनगंज–गढ़वा पथ को ठीक कर दिया गया। आप इस बात का फैसला कीजिये कि कोर्ट से सरकार चलेगी कि सरकार से सरकार चलेगी?

अध्यक्ष : मैंने कहा – जो शब्द मैंने कहा है कि वह समझ गए कि कल मैं उनसे इस पर वक्तव्य दिलाऊंगा।

श्री तुलसी सिंह : महोदय, मैं कह रहा था कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न सदन के सामने खड़ा किया है मैं उसका जवाब आपके माध्यम से देना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने सबसे पहले कहा कि शहरों की हालत खराब है और बाढ़ की सुरक्षा नहीं है। माननीय संदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जून के महीने में ही बाढ़ से सुरक्षा की परी तैयारी कर ली थी।

आज कोई ऐसी चीज नहीं है जबकि बाढ़ की स्थिति होने के वाबजूद भी ऐसी स्थिति नहीं आयी जिससे कहा जाय कि बाढ का मामला नियंत्रण से बाहर हैं। महोदय, उन्होंने कहा कि शहर का विकास पहले होना चाहिए और गांव का विकास बाद में होना चाहिए।

श्री चन्द्रमोहन प्रसाद : माननीय मंत्री उन्होंने कहा कि गांव के साथ साथ शहरों का विकास भी होना चाहिये।

श्री तुलसी सिंह : मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि गांव का भी विकास होना चाहिए लेकिन शहर पर ध्यान देना चाहिये। मैंने जो नोट किया है, मेरी बात सुनी जाय।

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : अध्यक्ष महोदय, जिस समय मैं बोल रही थी शायद माननीय मंत्री गौर से मेरी बातों को नहीं सुन रहे थे। इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि पहले शहरों का विकास होनी चाहिये तब गांव को। मैंने यह कहा था कि गांव का विकास होना चाहिये लेकिन शहरों का विकास समाप्त करके नहीं होना चाहिये।

श्री तुलसी सिंह : महोदय, इसमें कहां झगड़ा है। लेकिन प्रश्न यह है कि चार प्रतिशत लोग ही शहर में रह रहे हैं और अधिकांश लोग सैकड़े ९५ प्रतिशत गांव में रह रहे है।

कोई अच्छी सरकार होगी, जो जनता की सरकार होगी सैकड़े ९५ प्रतिशत लोगों को पहले सुविधा देगी, उन पर ज्यादा ध्यान देगी और महोदय उन्होंने यह बात भी कहा कि शहरों में नगरपालिकाओं का चुनाव नहीं हुआ। मैं माननीय सदस्या को बताना चाहता हूं कि जो नागरपालिका है लोकल बडीज है उनके चुनाव में क्यों देर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के संबंध में जो नियम था उस वजह से विलंब हुआ और इसमें बाधा पहूंची। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार की यह मान्यता है कि

कटिब्द्ध है और जब से यह राज्य सरकार आयी है सबसे पहले उसका ध्यान गरीबों की ओर गया है। सबसे पहले इसका ध्यान गरीबों के जो उपेक्षित वर्ग है पासी उसका टैक्स मांफी करने की तरफ गया। फिर जो हमारे मछुआरे हैं उनकी तरफ ध्यान गया। हमारी राज्य सरकार का, लालू जी का, राष्ट्रीय जनता दल का और राबड़ी देवी की सरकार की मान्यता और विश्वास है कि जबतक गांव के गरीब तबके के लोग आगे नही बढ़ेंगे तबतक इस राज्य का विकास नहीं होगा। महोदय, इसी दृष्टि से हमारे वित्त मंत्री ने कहा कि जब हम गद्दी पर १९९० में आये थे, उस समय क्या हालत थी। कि बोर्ड कौरपोरेशन में तनखवहाह नहीं मिलेगा, लाल बत्ती जलेगी।

श्री रामाश्रय प्र० सिंह : १९९० में ऐसी स्थिति थी कि एक एक भी बोर्ड और कौरपोरेशन का इम्पलाइज का सैलरी का पैसा बाकी नहीं था। गलत बयानी कर के अपनी अक्षमता को आप छिपाना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, आपने आश्वस्त किया था कि जिस दल के लोग नहीं बोल पाये हैं, मैं उनको समय दूंगा। हम लोगों को कब समय दिया जायेगा।

अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री तुलसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, राजाश्रय बाबू को मैं बताना चाहता हूँ कि जब 90 में सरकार बनी थी, उसमें कितना अन्डरटेकिंग लाभ में चल रहा था, कितना निगम का हिसाब अप-टू-डेट था, सारे के सारे निगम की हालत खराब थी।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं।

जबतक बहुमत वर्ग के लोग, स्वैच्छिक स्थानीय संस्थानों में उनकी भागीदारी सुनिश्यित नहीं होगी, इस राज्य, इस देश का विकास नहीं होगा। इसी दृष्टि से लालू जी के नेतृत्व ने राज्य सरकार ने जो पंचायत एक्ट बनाया है वह अन्य राज्यों में जो पंचायत एक्ट बना है उसमें सबसे प्रगतिशील और सबसे क्रांतिकारी एक्ट बनाया है। लेकिन महोदय जो लोग प्रतिक्रिया वादी, हैं जो परिवर्त्तन विरोधी हैं और जो साम्प्रदायिक लड़ाई लड़ने वाले हैं वे नहीं चाहते हैं कि कोई प्रगतिशील काम हो और इसलिये उन लोगो ने न्यायालय के जाल में संविधान के सेंच फंसा दिया हैं। महोदय, वहां से फैसला क्यों नहीं मिलेगा? महोदय, सरकार की चिंता है कि गरीबों का भला कैसे किया जाय लेकिन न्यायालय में मामला फंसा होने के चलते काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार की प्राथमिकता है कि जा गांव के गरीब किसान खेत मजदूर हैं जो बहुकत में हैं, महोदय, मोदी ने उसी क्रम में एक बात कहीं, वह मैं रेफरेंस मात्र के लिये कहना चाहता हूं कोई आलोचना के लिये नहीं। उन्होंने आवेश में का कि जेल भिजवा दिया, अब ३५६ भी लगवा देंगे। महोदय, मुझे आश्चर्य हुआ यह सुनकर कि जब लालूजी बैठते थे और जब मुकदमा चल रहा था तो मोदी जी का व्यान होता था कि सी0बी0आई0 के बारे में और उसी पर सी0बी0आई0 चलती थी। और आज उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सी0बी0आई0 इनके कहने से काईवाई की है। इन्होंने स्वतः माना है। इतना ही नहीं इन्होंने कहा कि दिल्ली की सरकार, बाजपेयी जी की सरकार जो मोदी जी कहेंगे वही करेगी। महोदय, यह मंशा की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि दिल की सच्चाई छिप नहीं सकती है। जब इंसान आवेश में आता है तो सच्ची बात सामने आ ही जाती है। मोदी जी की मंशा और जो इनके दल की नीति है वह उनके मुंह से सदन के सामने आ ही गयी। इसलिये महोदय, यह कहने में जरा भी दिक्कत नहीं है कि ये लोग प्रगतिशील तत्व हैं जो देश का विकास करना चाहते हैं उसको ये लोग बढ़ने देना नहीं चाहते हैं। महोदय, एक बात और कहना चाहता हूं कि गरीबों के विकास के लिये राज्य सरकार

श्री तुलसी सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं रामाश्रय बाबू को बताना चाहता हूँ कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो एकाएक बड़ा नहीं हो जाता है, जब कोई वृक्ष लगाते हैं तो एकाएक बहुत बड़ा नहीं हो जाता है, 90 में हमलोगों ने बीज को बोया तो इतना जल्दी फल थोड़े ही देने लगेगा।

(व्यवधान)

महोदय, मैं कह रहा था कि 92-93 में जो हमारी आर्थिक स्थिति थी, उसको हमारी सरकार ने ठीक किया, तब से लेकर आज तक लाल बत्ती नहीं जली। महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि 97-98 जो पहला वर्ष है, जब 1700 करोड़ रूपया विकास पर खर्च हुआ है, उससे पहले के वर्षों में कभी भी इतनी बड़ी राशि विकास के मद में खर्च हुई थी, यह मैं सदन को बताना चाहता हूँ। महोदय, हमारी योजना की राशि केन्द्र सरकार द्वारा 2400 के बाद 2900 हुआ, उसके बाद अब यह 4300 करोड़ रूपया का योजना स्वीकृत हुआ है, ये लोग इसके लिए हमारी सरकार को बधाई नहीं देंगे, ये लोग सिर्फ खार्मियों का ही जिक्र करते हैं, खूबियों को तरफ इनका ध्यान नहीं जाता है। महोदय, जो बिगड़ी हुई आर्थिक स्थिति पहले थी, उसको इस सरकार ने दुरूस्त किया है।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर सी0पी0एम0 एवं सी0पी0आई0 (एम0एल0) के माननीय सदस्यगण सदन से बर्हिगमन किये)

श्री तुलसी सिहं : महोदय, विपक्षी सदस्यों द्वारा बार-बार यह आवाज उठायी जाती रहती थी कि राज्य की आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है, कर्मचारियों को वेतन देने का भी सरकार के पास पैसा नहीं है, पैसों की लूट हो रही है। महोदय, मैं आज सदन को बताना चाहता हूँ कि आज जब हमारे पास पैसा काफी है, तो विपक्षी सदस्य कहते हैं कि पैसा खर्च नहीं हो रहा है। मैं कहना

चाहता हूँ कि क्या पैसा को इसी तरह लूटा दें। पैसा का सही ढंग से इस्तेमाल होना चाहिए पैसा को सही ढंग से न खर्च होना चाहिए, महोदय, जो बिगड़ी हुई व्यवस्था पहले थी, वह तो एकाएक ठीक नहीं हो सकता था? इसलिए आज सरकार ने सरकारी पैसे के खर्च में बहुत सी सावधानियाँ बरती है, व्यर्थ में पैसा बहने नहीं दिया जायेगा, व्यर्थ का पैसा जो खर्च किया जाता था, उसको राज्य सरकार द्वारा सुधारा जा रहा है और यह अब सुधर भी गया है। महोदय, इस वित्तीय वर्ष के लिए हमारे पास जो पैसा है, उसको हम गरीबों के विकास पर ज्यादा खर्च करेंगे, इसलिए आज इनलोगों में घबराहट है। ये लोग नहीं चाहते हैं कि गरीबों पर पैसा खर्च हो, ये लोग चाहते हैं कि बिचौलियों के माध्यम से ही गरीबों पर पैसा खर्च हो, ताकि बिचौलिये सभी पैसा खा जाय और गरीबों के पास उसका सही हक, उसका सही विकास न हो सके, इसलिए हाज इनलोगों में घबराहट है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राधाकृष्ण किशोर ने जो ध्यान आकृष्ट किया है कि विशेष अंगीभूत योजना के लिए जो सहायता राशि केन्द्र सरकार से मिलता है, वह आपके पास विचाराधीन है, मैंने लिखकर कहा था कि इसकी जांच की जायेगी, सरकार कोई भी बात को छिपाना नहीं चाहती है। इसी तरह से महोदय, रेडी टू इट फूड के संबंध में जो बात कही गयी है कि सड़ा हुआ अन्न मिलता है, इसकी जांच भी हुई थी, सड़ा हुआ होने के बाद भी इसकी आपूर्ति की जा रही है। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि 1995 में मैंने अपनी अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाई थी, उसमें मौडर्न फूड कंपनी के सभी संबंधित लोग शामिल भी हुए थे।

उन्होंने निर्णय लिया था कि ज्यों की बिहार केन्द्रों में दोनों टीम जायेंगे, नमूना लेने का काम करेंगे और तत्काल उन्होंने नमूना लीं। महोदय, उससे ....

(व्यवधान)

श्री जवाहार प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर हूँ। मेरी व्यवस्था है

कि बिहार में कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां बिना पैसा का काम होता हो। बिना पैसा का काम नहीं होता है।

श्री तुलसी सिंह : हमारे माननीय सदस्य श्री राधा कृष्ण किशोर ने जो कहा था, उस संबंध में मैंने बतलाया कि वर्ष 1995 में मैं कल्याण मंत्री की हैसियत से एक बैठक बुलायी थी जिसमें मोडर्न फुड कंपनी के लोग थे, कल्याण सचिव थे और अन्य संबंधित पदाधिकारीगण भी थे। उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि नमूना लिया जायेगा जिसके आधार पर 12-14 नमूने लिए गए। यहां तक कि इससे ज्यादा नमूने लिए गए। उनकी रिपोर्ट हमारे पास आई है। एक भी रिपोर्ट में गलत टीका-टिप्पणी नहीं है। भारत सरकार की जो यह संस्थान है, उसका कार्यालय दिल्ली और कलकत्ता में है। जब हमने जिक्र किया है, फुड नमूना की बात की है, तो मैं कहना चहता हूँ कि उसको मैंने खुद खाया था।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सीरियस बात है जिसकी ये अवहेलना कर रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित अनजाति का 8 करोड़ रूपया रिलायंस और टाटा में जमा हो गया है।

श्री तुलसी सिंह : महोदय, मैं इसकी समीक्षा कर रहा हूँ। 10 मिनट में सारे विभागों की जानकारी देना क्या संभव है? उन्हें विशेष कार्य में लगाया गया था। जिसका जवाब देना चाहिए, उसका जवाब नहीं आया। यह जांच की बात है। हमारे अफसर, जिन्होंने बिना जानकारी के गलत ढंग से रिपोर्ट भेजी है, उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

(व्यवधान)

श्री तुलसी सिंह : महोदय, सरकार को बदनांम कि करने का काम किया जा रहा है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूँ कि एस0सी0, एस0टी0, निगम का जो पैसा है, उससे रिलायंस, टाटा और टाईमेक्स कंपनी का शेयर खरीदा गया है। यह बात स्पष्ट करें कि उस पैसे से टाटा, टाईमेक्स और रिलायंस का शेयर खरीदा गया या नहीं? अगर खरीदा गया तो क्यों खरीदा गया?

श्री तुलसी सिंह : महोदय, मैं रामाश्रय बाबू की बात से सहमत हूँ कि अजाबिनी के पैसे से शेयर नहीं खरीदा गया है बल्कि दूसरे अंडरटेकिंग्स में लगाया गया है।

(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : दूसरे अंडरटेकिंग में क्यों लगाया गया?

श्री तुलसी सिंह : महोदय, रामाश्रय बाबू ने जो सूचना दी है अजाविनी और विशेष अंगीभूत के संबंध में, तो मेरा कहना है कि इसकी जांच के लिए विशेष समिति गठित कर दी गई है और मैं समझता हूँ कि इस पर विशेष विचार-विमर्श की आवश्यकता नहीं है। वह मामला जांच के क्रम में आ जायेगा।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : महोदय, यह गरीबों का पैसा है, गरीबों के लिए सुरक्षित है तो उस पैसे से टाईमेक्स का शेयर खरीदा जायेगा।

(व्यवधान)

श्री तुलसी सिंहः माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है कि बजट का 80 प्रतिशत रूपया नन-प्लान पर खर्च होता है और वह सब रूपया मंत्री और अफसर पर खर्च होता है। महोदय, आप भी जानते हैं और सदन भी जानता है कि सरकार न सिर्फ तनख्वाह पर ही खर्च करती है बल्कि विकास का काम पर खर्च करती है। जो योजनायें बराबर चलनेवाली हैं, उसे प्लान से नन-प्लान में ले जाते हैं जिससे विकास कार्य होता है। उससे तनख्वाह भी

दिया जाता है। राज्य सरकार ने स्पष्ट जिक्र कर दिया है कि यह पैसा तनख्वाह और विकास पर खर्च किया गया है। बजट में इसकी चर्चा की गई है। इसमें कहीं कोई गड़बड़ी होने की बात नहीं है। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि प्लान का जो 20 प्रतिशत रूपया है, उसको सरकार नन-प्लान में खर्च कर सकती है जिससे विकास का काम होता है और उसी से तनख्वाह भी दिया जाता है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, कितना-कितना खर्च होगा, यह माननीय मंत्री स्पष्ट करें। जिला योजना का पैसा विधायकों की अनुशंसा पर कितना-कितना खर्च होगा?

श्री तुलसी सिंह : महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य जानते हैं इस बात को कि जो जिल योजना विकास पर्षद है उसे मेम्बर एम0एल0ए0 और एम0पी0 होते है। अब प्रमुख है नहीं। दूसरा कोई मेम्बर नहीं होता है। सिर्फ एम0एल0ए0 है, एम0पी0 हैं, इनके बीच में योजना बनती हैं। सब पैसा दिया हुआ है और यह पूरे देश में चल रहा है।

(व्यवधान)

यह पहले से भी निर्देश है कि हरेक क्षेत्र में बराबरी का हिस्सा रखा जायेगा। मैं फिर निर्देश दे दूंगा कि जिला योजना का पैसा संख्या के बल पर प्रखंडों में बांटने की व्यवस्था की जाये। इस में किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है। यह मैंने व्यवस्था किया है।

श्री शिवनाथ वर्मा : महोदय, हमलोगों को अनुभव है कि जिला योजना का पैसा क्लक्टर अपने हिसाव से डायभर्ट करते है। न कोई मीटिंग होती है, न कोई योजना बनती है। इस पर माननीय मंत्री जी जवाब दें।

श्री तुलसी सिंह : मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हर जिले में प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला विकास बनी हुई है।

(व्यवधान)

बिना जिला विकास पर्षद के एक पैसा खर्च विकास का नहीं हो सकता है। कभी कभी कलक्टर लोग इस विश्वास पर कि उनको अनुशंसा मिल जायेगी, अनुशंसा की प्रत्याशा में खर्च करते है और उसकी स्वीकृति तो लेते है।

(व्यवधान)

श्री शिवनाथ वर्मा : मैं इस को चुनौती देता हूं।

श्री तुलसी सिंह : महोदय, मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा हुआ है और जिला विकास पर्षद ने स्वीकृति नहीं दिया है तो विशेष सूचना देंगें, मैं निश्चित रूप से नियम तोड़नेवाले अधिकारी पर कार्रवाई करूंगा।

(व्यवधान)

श्री तुलसी सिंह : महोदय, राज्य सराकार, को प्राथमिकताएँ है गांवों, गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग के लोग और हमारा बजट, हमारी योजनायें, हमारी नीति सब उसी के आधार पर बन रही है और इसीलिए मैंने शुक्रवार को कहा था हम निर्गुण नहीं बोलते हैं, सगुण काम करते हैं। हम जो कह रहे है, वहीं कर भी रहे हैं। महोदय, 1990 के पहले इन्दिरा आवास में लोग जाना पसंद नहीं करते थे। लेकिन आज इन्दिरा आवास के लिए मांग होती है। कोई फर्क पहले और आज में है या नहीं? पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी डोम के घर गये, मुशहर जाति के घरों में गये, उनके साथ बैठे, खाना खाये। महोदय, मैं आपके माध्यम से श्रीमती चन्द्रमुखी देवी जी से आग्रह करता हूं कि वे अपना कटौती का प्रस्ताव ले लें।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या श्रीमती चन्द्रमुखी देवी। क्या आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस लेना चाहती है?

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : अध्यक्ष महोदय, जो मंत्रिमंडल इस नीति पर चले कि-

किस किस को याद करे,
किस किस को रोयें,
आराम बड़ी चीज है,
मुंह ढंक कर सोये।

महोदय, मैं इस सरकार के लिए एक पैसा देने की आवश्यकता नहीं समझती हूं। अध्यक्ष महोद्य, आज की सरकार इस सदन के अंदर बैठ कर गलत ब्यानी करती है।

अध्यक्ष : असल में आपने जो बोल दिया। एक कहावत है कि-

रातसईया को दोहरे,
अरूणावत के तीर,
देखन को छोटन लगे,
घाव करे गंभीर।

श्रीमती चन्द्रमुखी देवी : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री महोदय सदन में उत्तर दे रहे थे, सदन में वे गलत बयानी कर रहे थे। जिस सरकार में माननीय मंत्री महोदय को इतनी सी बात की जानकारी नहीं हो कि उनके प्रशासन के अधिकारी क्या कर रहे हैं उस सरकार को पैसा देने की क्या आवश्यकता है? इनको यह पता नहीं कि जिला योजनाओं की राशि है वह केवल एकमात्र कलक्टर की अनुशंसा से चलती है। इसके लिए विधायकों की अनुशंसा नहीं ली जाती है।

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि इसकी वे जांच पड़ताल करेंगे। विभाग की तरफ से कई आश्वासन दिए गए हैं। जो सरकार गरीबों के बीच में बंटने वाली इन्दिरा आवास में बंदरबाट करती हो, वी0डी0ओ0 के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखे, एक मिनट में मेरी बात सुन लिजिए, उस सरकार को गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं में लूट-खसोट

को रोक नहीं सके तो मैं सहीं समझती हूं कि उस सरकार की पैसे देने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कटौती प्रस्ताव को वापस लुंगी, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि:-

"इस शीर्षक की मांग 10 रूपये से घटायी जाय।"

"प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।"

अध्यक्ष : अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं।

प्रश्न यह है कि :-

"प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजना/योजनाओं के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग" के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए बिहार विधान मंडल द्वारा अनुकोदित बिहार विनियोग अधिनियम, 1998 के उपबंध के अतिरिक्त 45,74,000 (पैंतालीस लाख, चौहत्तर हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान की जाए।"

"प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।"

मांग स्वीकृत हुई।

(कृषि विभाग)

(स्वीकृत)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि-

"प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण के अनुदान तथा नियोजन की मांगों की अनुसूची में सम्मिलित योजनाओं के लिए कृषि विभाग के संबंध में 31 मार्च, 1999 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान में जो व्यय होगा उसकी पूर्त्ति के लिए बिहार विधान मंडल द्वारा अनुमोदित बिहार विनियोग अधिनियम, 1998 के उपबंध के अतिरिक्त 16,64,59,000/-(सोलह करोड़, चौंसठ लाख, उनसठ हजार) रूपये से अनधिक अनुपूरक राशि प्रदान